पेरिस ओलंपिक 2024 की बुधवार यानी 24 जुलाई को फुटबॉल और रग्बी मैच के साथ शुरुआत हुई। खेलों के महाकुंभ का फैंस को जितना इतंजार था, उस हिसाब से खेलों की शुरुआद विवाद के साथ हुई।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्षः29 अंकः226 दिनांकः27-07-2024 शनिवार मूल्यः1 रूपया 50 पैसा पृष्ठः4 अहमदाबाद M

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की अदालत में पेश होने आए थे। राहुल गांधी सुल्तानपुर शहर के बाहरी इलाके में एक मोची की दुकान पर रुके और उसका हालचाल जाना।

मुंबई में भारी बारिश....पुलिस की लोगों को सलाह घर पर ही रहे

मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया

मुंबई (ईएमएस)। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद पुलिस ने मुंबई निवासियों को शनिवार सुबह 8:30 बजे तक घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। यह सलाह भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद है। पिछले 24 घंटों में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक मुंबई शहर में 44 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 90 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 89 मिमी बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का आकलन कर रायगढ़ कलेक्टर को बाढ़ प्रभावित निवासियों की सहायता करने का निर्देश दिया। भूस्खलन के कारण रायगढ़-पुणे मार्ग पर तम्हिनी घाट पर यातायात रोक दिया गया।

पुणे में सड़कों पर और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खडकवासला बांध और जलग्रहण क्षेत्र में काफी बारिश हो रही है। जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त अलर्ट पर हैं, सीएम शिंदे ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य समकक्ष की टीमों को तैनात किया गया है, और सेना की एयरलिफ्टिंग टीमें स्टैंडबाय पर हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा संदेश

मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया, आईएमडी ने कल सुबह 8:30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। सभी मुंबईवासियों से अनुरोध है कि जब तक जरूरी न हो, घर के अंदर ही रहें। कृपया सुरक्षित रहें। आपात स्थिति के लिए 100, 112 डायल करें।

रनवे परिचालन को पहले सुबह 8:32 बजे से सुबह 8:43 बजे तक 11 मिनट के लिए रोका गया, और फिर सुबह 10:36 बजे से 10:55 बजे तक 19 मिनट के लिए रोका गया क्योंकि दृश्यता 300 मीटर तक गिर गई और रनवे विजुअल रेंज (आरवीआर) गिर गई।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरलाइन वेबसाइटों और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें और मुंबई में चल रही भारी बारिश और यातायात की भीड़ के बीच हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनाएं। मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने पुणे शहर और घाट इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के लिए रेड अरल्ट जारी किया गया है। भोर, वेल्हा, मावल, मुलशी, खड़कवासला, हवेली, खेड़, अम्बेगांव, जुन्नार, पुणे शहर और पिंपरी चिंचवाड़ में सभी आंगनवाड़ी, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनें, बस, फ्लाइट्स समेत तमाम ट्रांसपोर्ट बाधित हुए हैं। लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है। रायगड के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है। महाराष्ट्र में चार नदियां भी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। राहत कार्य के लिए महाराष्ट्र में आर्मी को लगाया गया है।

एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया

दांबुला / श्रीलंका(ईएमएस)। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वूमेन्स एशिया कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को रंगिरि दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए महज 81 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 11 ओवर में ही हासिल कर लिया। फाइनल में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा।

भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए, जिसमें 9 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा। वहीं शेफाली वर्मा 26 रन पर नाबाद रहीं। शेफाली ने 28 गेंदों की पारी में 2 चौके लगाए। इन दोनों ने धांसू बल्लेबाजी करके बांग्लादेश को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 80 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए कप्तान निगार सुल्ताना ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। इसके अलावा शोर्ना अख्तर (नाबाद 19 रन) ही दोहरे अंकों में पहुंच सकी। भारत की ओर से तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और स्पिनर राधा यादव ने तीन-तीन विकेट लिए। जबकि पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा को एक-एक सफलता मिली।

दिल्ली में भाजपा और संघ के प्रमुख नेताओं के बीच बैठक -योगी आदित्यनाथ के भाग्य का होगा फैसला

उत्तर प्रदेश के संगठन और सत्ता में बड़े फेरबदल की तैयारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भाजपा में इन दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है।पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के बीच में लगातार मतभेद की खबरें बाहर आ रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में दोनों मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। तीनों के बीच मतभेद की खबर सुर्खियों में है। मीडिया में कहा जा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना चाहता है। दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में हैं।कहा जा रहा है, कल एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में होने जा रही है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता और संगठन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर दिल्ली का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बड़ी संख्या में भाजपा के उत्तर प्रदेश के विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। भाजपा के अंदर उत्तर प्रदेश की सत्ता और संगठन को लेकर जो तूफान पार्टी के अंदर मचा हुआ है। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई है। कहा जा रहा है, भाजपा के बहुत सारे विधायक बगावत की मुद्रा में है। ऐसी स्थिति में भाजपा हाईकमान के लिए उत्तर प्रदेश का मामला सुलझाने की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। शनिवार को इस मामले में कोई बड़ा निर्णय भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ले सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली पहुंचने के बाद इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यह कहा जा रहा है, एक-दो दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा हाईकमान कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है। भाजपा हाईकमान और संघ इस मामले में भी चर्चा कर रहा है। यदि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है। तो इसका असर हरियाणा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से पड़ेगा। इसका भी आकलन किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं।

सात लाख अदालती मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार ,वित्त, रेलवे और रक्षा से संबंधित सबसे ज्यादा मामले

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र करीब सात लाख अदालती मामलों में पक्षकार है। इसमें रक्षा, रेलवे और वित्त मंत्रालय के मामले 50 प्रतिशत से अधिक हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा में मंत्री मेघवाल द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी मंत्रालयों से जुड़े कुल 6,98,904 मामले अदालतों में लंबित हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग पक्षकार हैं। इन मामलों में सबसे अधिक 57 प्रतिशत मामले तीन मंत्रालयों वित्त, रेलवे और रक्षा से संबंधित हैं।

हालांकि, उन्होंने कानून मंत्रालय के कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) के डेटा की सहायता से आंकड़े पेश किए, इसपर सभी मंत्रालय अपने स्वयं के मामलों का विवरण दर्ज करते हैं।

एलआईएमबीएस डेटा के अनुसार, 19 जुलाई तक कुल 6,98,904 मामले अदालतों में लंबित थे, जिसमें केंद्र सरकार एक पक्षकार थी। इसमें सबसे अधिक लंबित मामले वित्त मंत्रालय से जुड़ा हैं, जिनकी संख्या 1,89,289 है। इसके बाद रेलवे का नंबर आता है, जिसके 1,14,557 मामले लंबित है। वहीं, रक्षा के भी 95,467 मुकदमे लंबित हैं।इनके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 79,988 मामले और गृह मंत्रालय के 24,409 मामले लंबित हैं। विभिन्न हाईकोर्ट में कुल 2,53,073 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 17,779 है।

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी बोले अग्निवीर पर झूठ फैला रहा विपक्ष

द्रास (ईएमएस)। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1विनोद उपाध्याय / 26 जुलाई, 2024 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वे कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे। मैं जहां खड़ा हूं, वहां से आतंक के आकाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना का रिफॉर्म्स हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रहीं। कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। कुछ लोगों की मानसिकता यही थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए इसे हमने साकार किया है। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है।

टनल की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 15,800 फीट है। यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख की जास्कर वैली से जोड़ेगी। 4.1 किमी लंबी यह टनल निमू-पदुम-दारचा रोड पर बनाई जाएगी। इसे बनाने में करीब 1681 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीमा सडक संगठन (बीआरओ) करीब दो साल में बनाकर तैयार करेगा। इलाके में साल के चार-पांच महीने बर्फ जमी रहती है। टनल बन जाने के बाद यहां सालभर आवाजाही की जा सकेगी। शिंकुन ला टनल एक ट्विन-टयूब डबल लेन टनल होगी। इसमें हर 500 मीटर के बाद क्रॉस पैसेज होंगे। इसके अंदर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं होंगी।

अग्निपथ योजना पर खुलेआम झूठ बोल रहे पीएम मोदी : खड़गे

पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के बयान का ज़िक्र

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कारगिल विजय दिवस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आलोचना पीएम मोदी द्वारा द्रास में एक संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना की आलोचना के लिए विपक्ष पर निशाना साधकर सेना को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जैसे अवसरों पर भी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं।

खरगे ने कहा कि पीएम मोदी का दावा कि उनकी सरकार ने सेना के आदेश पर अग्निपथ योजना लागू सरासर झूठ और हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का अक्षम्य अपमान है। खरगे ने कहा कि मोदी जी, आप ही हैं जो झूठ फैला रहे हैं! पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल एमएम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 75 प्रमतिशत भर्तियों को स्थायित्व के लिए लिया जाना था और 25 प्रतिशत लोगों को 4 साल बाद जाने दिया जाना था। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उलटा कर योजना को तीनों सशस्त्र बलों के लिए जबरन लागू कर दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल नरवणे ने अपनी पुस्तक में, इस मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक दिया है, कहा है कि अग्निपथ योजना सेना और नौसेना और वायु सेना के लिए चौंकाने वाली थी।

कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं अखिलेश यादवः केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ (ईएमएस)। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के मोहरा बताए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है खिलेगा,खिलता रहेगा। दरअसल, कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान की खबरों पर कहा था कि बीजेपी में झगड़ा दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच है। अखिलेश ने कहा कि केशव प्रसाद सिर्फ मोहरा हैं।

संसद में किसानों के मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा

नई दिल्ली(ईएमएस)। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामजी लाल सुमन ने 12 जुलाई 2000 को किसानों की समस्याओं पर बनी कमेटी की बैठकों के ब्यौरे को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान की तरह है और किसान की सेवा हमारे लिए पूजा जैसी है। उन्होंने कहा कि इस समिति का गठन तीन उद्देश्यों- एमएसपी उपलब्ध कराने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ कृषि मूल्य को अधिक स्वायत्तता और कृषि वितरण प्रणाली के लिए सुझाव देने के लिए। उचित दाम देने के लिए समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि समिति की 22 बैठकें हो चुकी हैं। समिति जो सिफारिश देगी, उस पर विचार किया जाएगा। इस पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये अनिश्चितता का वातावरण है। ये कब दूर होगा। ये जो किसान को भगवान बता रहे हैं, इनको किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। सीधा जवाब दीजिए कि आप एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। बचिए मत। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राम, शिव से सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में शिवराज ने कहा कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं।

सरकार की छह सूत्रीय रणनीति

कृषि मंत्री ने कहा की कृषि के लिए सरकार की छह सूत्रीय रणनीति है। शिवराज ने उत्पादन बढ़ाने से लेकर लागत घटाने तक के उपाय गिनाए और कहा कि हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदीजी से बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं। उचित दाम देने के लिए समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ाए जाने के आंकड़े गिनाए और कहा कि इन 23 फसलों के दाम देख लीजिए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज ने कहा कि जब सुरजेवालाजी की सरकार हुआ करती थी, उससे दोगुने एमएसपी दिए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हम किसान के हित में लगातार फैसले लेते जा रहे हैं।उन्होंने किसानों के लिए सम्मान निधि के साथ ही गेहूं-धान की खरीद बढऩे का भी जिक्र किया। शिवराज ने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर पर 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। और भी कदम जरूरी हैं जिन्हें लेकर सरकार गंभीर है। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला और विपक्ष के अन्य सांसदों ने एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने दोनों पक्ष के सदस्यों से बैठने के लिए कहा और नेम करने की चेतावनी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुअर, मसूर, उड़द किसान जितना उत्पादन करेगा, ये सरकार खरीदेगी।

विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा

कृषि मंत्री ने यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में एमएसपी पर हुई खरीद के आंकड़े गिनाए और कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस पर सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे पर सभापति ने कहा कि सप्लीमेंट्री गन की नोक पर लोगे, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे की तरह जिद क्यों कर रहे हो रणदीप, नो। शिवराज ने यूपीए सरकार का कैबिनेट नोट भी टेबल पर रखा जिसमें लागत पर 50 फीसदी बढ़ाकर एमएसपी निर्धारित करने से इनकार की बात कही गई थी। उन्होंने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने से इनकार का भी उल्लेख किया। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये किसान के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं, देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसान की बेहतरी के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

सपा का दावा - मनोज पांडेय बनेंगे यूपी की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री

नई दिल्ली (ईएमएस)। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि मनोज पांडेय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडेय ने सपा से बगावत कर बीजेपी का रुख कर लिया था। वे रायबरेली स्थित ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे।

सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- राजनैतिक हलकों में चर्चा है कि मनोज पांडेय की भाजपा से जो डील हुई उन्हें उप-मुख्यमंत्री बनाया जायेगा। ब्रजेश पाठक बसपा से भाजपा में 2017 में गये और मनोज पांडेय ने 2024 में सपा से भाजपा में शामिल हुए हैं।

सपा नेता ने लिखा कि- ब्रजेश पाठक केशव गैंग के सदस्य के रूप में योगी जी को हटाने की मुहिम का हिस्सा हैं। जानकारी जो दिल्ली से आ रही है दोनों उप मुख्यमंत्री गुजरात और बिहार के तर्ज पर हटाये जा सकते हैं। पाठक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ। दिनेश शर्मा को निबटा कर कुर्सी हासिल की अब मनोज पांडेय इन्हें निबटाने जा रहे हैं। ये रस्साकशी बीजेपी को पाताल में ले जायेगी।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी नेता मनोज पांडेय के मुलाकात की एक एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए आईपी सिंह ने यह दावा किया। गुरुवार को ही ब्रजेश और मनोज की मुलाकात हुई थी।

कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला- सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा- कांवड़ सिर्फ तीन राज्यों से गुजरते हैं। यह सिर्फ खाने-पीने के लिए नहीं है। केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा- एक कांवडिए ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है। खाना क्या है यह पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया।

जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल को भी दो हिस्सों में बांटा जाएगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे पश्चिम बंगाल के आठ जिलों को पूर्वोत्तर का हिस्सा मानें, जिनकी सीमाएं सिक्किम से लगती हैं।

बैठक के बाद मजूमदार ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव सौंपा है और उन्हें बताया कि आखिर क्यों उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर का हिस्सा माना जाना चाहिए और दोनों के बीच क्या समानताएं हैं। अगर वे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो बंगाल के इस पिछड़े इलाके को केंद्र से अधिक धन मिलेगा। मेरा मानना है कि राज्य सरकार सहयोग करेगी।

यह एक सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि यह भविष्य में भाजपा द्वारा आधिकारिक तौर पर राज्य के विभाजन की मांग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने मजूमदार के साथ करीब आधे घंटे बिताए, जिससे यह पता चलता है कि वे प्रस्ताव को कितना महत्व देते हैं।

मजूमदार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उनका यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो जाता है। वे पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, जिससे मांग का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। इससे पहले मजूमदार को भाजपा सांसदों द्वारा अलग उत्तर बंगाल की कई मांगों को व्यक्तिगत राय के रूप में खारिज करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि वे बालुरघाट निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, जो भी उत्तर बंगाल के अंतर्गत आता है।

संविधान हत्या दिवस के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संविधान हत्या दिवस के विरोध में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। अगले दिन 13 जुलाई को सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था। सरकार ने इसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ लडऩे वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि बताया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कि अधिसूचना आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है।

दुनिया की 73.3 करोड़ आबादी खाली पेट सोने को मजबूर

पिछले 5 वर्षों में 233 करोड लोग कुपोषण के शिकार

जिनेवा (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र संघ की पांच एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2024 की रिपोर्ट में विश्व खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कॉविड-19 के पहले जो स्थिति थी। उससे भयावह स्थिति में 2024 मे हो गई है।

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 11 इंसान मे 1 इंसान खाली पेट सोने के लिए मजबूर हो गया है। दुनिया के देशों में 73.3 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी आबादी अल्प पोषण के शिकार है। 2019 में ऐसे लोगों की संख्या मात्र 15.2 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट में अफ्रीका के देशों की स्थिति इसमें सबसे ज्यादा खराब है। यहां हर पांचवा व्यक्ति भुखमरी का शिकार है।

दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों द्वारा जिस तरह से खाद्य पदार्थो विक्रय किये जा रहे हैं। उनके 90 फ़ीसदी उत्पाद कुपोषण को बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। पेकफूड के उत्पाद कुपोषण बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 233 करोड़ आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें नियमित रूप से संघर्ष करना पड़ रहा है। दुनिया के 86.4 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से गुजर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सारी दुनिया के देश कुपोषण के मामले में 2008-09 की तुलना में काफ़ी नीचे चले गए हैं। पिछले 15 वर्षों में हालत में सुधार होने थे। उससे भी खराब स्थिति में दुनिया के देश पहुंच गए हैं। दुनिया के लिए यह चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है।

राहुल गांधी अचानक पहुंचे मोची की दुकान, ठीक किए पुराने जूते

सुल्तानपुर (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पेश हुए। सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ वापस लौट रहे थे। इस दौरान जब उनका काफिला कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचे तो चारों तरफ हलचल मच गई। अचनाक उनका काफिला चेत राम मोची की दुकान के पास रुक गया। दुकान पर राहुल गांधी पुराने जूते को ठीक करते दिखे। उनसे बातचीत की। वहां पांच मिनट रुककर राहुल ने उनसे व्यापार के बारे में बातचीत की, सेल्फी लिया। इसके बाद उनका काफिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए निकल गया।

रायबरेली सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट रूम 16 मिनट रुककर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया उसके बाद उनका काफ़िला वापस लखनऊ के लिए चल पड़ा। राहुल को पूर्वांचल के रास्ते लखनऊ एयरपोर्ट जाना था। राहुल गांधी का काफ़िला सुल्तानपुर से करीब 13 किमी दूर कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो उन्होंने बाए हाथ पर मोची की दुकान देखते ही गाड़ी रुकवाया और उतर कर सीधे चेत राम मोची के पास पहुंचे।

राहुल गांधी का काफिला रुकते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ आसपस जमा हो गई। चेत राम की गुमटी पर वे पांच मिनट रुके, बातचीत की, सेल्फी ली और फिर गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

चेत राम मोची ने बताया कि जिस जूते को हम सील रहे थे, राहुल ने उसे छूकर देखा। उन्होंने पूछा कि कैसे बनाते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि घर का भरण-पोषण कैसे चलता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात पर मोची चेत राम ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमने उनसे (राहुल गांधी) बोला है कि मैं पूंजी से कमजोर हूं, गरीब हूं। हमारी थोड़ी मदद कीजिए। मैंने उन्हें जूतों की सिलाई करके दिखाया। राहुल गांधी ने भी उसे छुआ।

विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार का मामलाः केंद्र, बंगाल-केरल के राज्यपालों से मांगा जवाब

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों के सचिवों से विधेयकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर जवाब मांगा है। राज्य सरकारों ने इस मामले में याचिका दायर की थी, इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किए। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध होता है, राज्यपाल कार्यालय विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राज्य सरकारों ने राज्यपालों द्वारा कई विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही कथित देरी पर चिंता जताई। यह विवाद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूरी न दिए जाने से जुड़ा है। राज्य सरकारों का आरोप है कि राज्यपाल इन विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, जिससे जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए अहम विधायी उपायों में देरी हो रही है। राज्य सरकारों की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल कार्यालयों और केंद्र को नोटिस जारी किया है।

बीजेपी का विरोध रह गया धरा......राम नगर जिले का नाम बदला गया

बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक कैबिनेट ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी। फैसले की जानकारी देकर कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि ब्रांड बेंगलुरु को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा, बेंगलुरू ब्रांड को ध्यान में रखकर कैबिनेट ने रामनगर के विधायकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया है। हालाँकि, मंत्री ने स्पष्ट किया, यह केवल नाम का परिवर्तन है और बाकी तालुके वहीं रहने वाले है। पाटिल ने स्पष्ट किया, राजस्व विभाग इस अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा और केवल जिले का नाम बदलेगा। हालांकि, भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है। इस महीने की शुरुआत में, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का प्रस्ताव सौंपा था। रामानगर जिले में पांच तालुक हैं, रामानगर, चन्नापटना, मगदी, कनकपुरा और हारोहल्ली।

भाजपा और जेडीएस इस लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी। कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करना चाहती है क्योंकि इसमें राम है। कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने कहा कि वे केवल इस बदलना चाहते हैं क्योंकि रामनगर के नाम में राम है।

जन हितैषी

खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार मिला राज्यों को

सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्य वाली खंडपीठ ने 8+1 से फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस फैसले में स्पष्ट किया गया है। रॉयल्टी, टैक्स के दायरे में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के एक फैसले में कहा था, कि रॉयल्टी भी एक टैक्स है। जिसे 09 सदस्यों की संवैधानिक खंडपीठ ने सही नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, कि सरकार को जो भी भुगतान किया जाता है उसे टैक्स नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने गुरुवार को जो फैसला दिया है, उसके अनुसार संविधान ने खनिज और खदानों से निकलने वाले उत्पाद और खनिज भूमि पर राज्य सरकारों के अधिकार को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, कि राज्यों को रॉयल्टी वसूल करने का संवैधानिक अधिकार है। रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता है। नौ जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। इसमें एक जज बीवी नगरत्ना का फैसला अलग था। उनके फैसले में यह कहा गया है, कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। वहीं आठ जजों का फैसला है, कि राज्यों का यह संवैधानिक अधिकार है। आठ जजों ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, कि संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 50 के अनुसार संसद के पास खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब स्पष्ट हो गया है कि रॉयल्टी को टैक्स के दायरे के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। खनिज भूमि और खनिज उत्पाद पर राज्य सरकारों का अधिकार है। रॉयल्टी एक अधिकार है। रॉयल्टी पर सरकार, पट्टेदाता और जमीन मालिक का अधिकार होता है। इस भुगतान को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। संविधान पीठ के नौ जजों की पीठ ने इस विवादास्पद मुद्दे पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का पक्ष काफी सूक्ष्मता के साथ सुना। कई दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रही। इसमें विवाद का विषय रॉयल्टी और खनिज भूमि केंद्र एवं राज्य के अधिकार को लेकर सुनवाई हो रही थी। खनिज अधिनियम 1957 के तहत टैक्स और रॉयल्टी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी थी। देश की सभी खनिज भूमि पर राज्य सरकारों का अधिकार है। राज्य सरकारों को इस मामले में रॉयल्टी वसूल करने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों को होगा, जहां बड़ी मात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध है। इस फैसले के बाद राज्यों को कानून बनाने और खनिज उत्पाद पर रॉयल्टी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी यह सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना है, कि यह अधिकार राज्यों को कब से प्राप्त होगा। राज्यों द्वारा पूर्ववर्ती समय से रॉयल्टी वसूल करने की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देना है, कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भूतलक्षी होगा या भविष्य में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यों का आर्थिक आधार मजबूत होगा। केंद्र एवं राज्यों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। इसके साथ ही रॉयल्टी और टैक्स की जो परिभाषा दी गई है, इसका असर केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी अधिकारों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर लंबे समय तक सुनवाई करके संविधान और विभिन्न कानून के हर पहलुओं पर विचार किया है। इस सुनवाई में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकार को लेकर भी गहन सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खनिज मामलों को लेकर जो विवाद केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच में चले आ रहे थे, इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा निजी भूमि के मालिक भी शामिल होते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब बहुत सारे विवाद निपट जाएंगे।

छद्म एवं पाखण्डी बाबाओं से मुक्ति की सार्थक पहल

भारतीय हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) की ओर से चौदह महामण्डलेश्वरों और संतों के निष्कासन की ताजा कार्रवाई पाखण्डी एवं छद्म बाबाओं से समाज को मुक्त करने का सराहनीय कदम है। अखाड़ा परिषद की गोपनीय जांच में अखाड़ों से जुड़े ये संत धार्मिक कार्यों के बजाय धनार्जन एवं अधार्मिक कार्यों में लिप्त पाए गए। ऐसे ही अन्य बाबाओं पर व्यभिचार, दुष्कर्म, जादू-टोटके व दूसरे अनैतिक कार्यों के भी आरोप लगते रहे हैं। इनके अलावा सौ से अधिक संतों को अखाड़ा परिषद ने नोटिस भी दिया है। निष्कासित किए गए संतों को अगले साल होने वाले कुंभ में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अखाड़ा परिषद की ताजा कार्रवाई इस तरह के कथित धर्मगुरुओं पर लगाम लगाने की प्रभावी कोशिश मानी जाएगी। इस तरह के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए, ताकि छद्म एवं पाखण्डी धर्मगुरुओं से समाज को मुक्ति मिल सके। आम लोगों में भी विवेक का जागरण जरूरी है, ताकि धर्म को विकृत करने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

अखाड़ा परिषद ने कुल चौदह ढोंगी संतों की एक सूची मीडिया में जारी की है। सूची में जेल की हवा खा रहे बाबा रामपाल, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसां, आसाराम, नारायण साईं व असीमानंद के अलावा निर्मल बाबा, राधे मां और कई ऐसे इच्छाधारी बाबा शामिल हैं, जो पिछले कुछ सालों में अपनी करनी के चलते विवादों में रहे हैं। गोलगप्पा खिलाकर लोगों की हर समस्या का समाधान करने वाले निर्मल बाबा जैसे ढोंगियों के झांसे में लोग कैसे खिंचे चले आते हैं, इस पर भी अखाड़े की ओर से कई चौंकाने वाले तथ्य बताए गए हैं। उनका मानना है कि राधे मां और निर्मल बाबा जादू-टोटके से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। बाबाओं की कारस्तानियों ने सबको सकते में डाल रखा है। महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करना इन बाबाओं की दिनचर्याओं में शामिल था। लाज-शर्म की वजह से कुछ महिलाएं नहीं बोलती थीं, उन्हीं का ये बाबा फायदा उठाते थे। इन बढ़ती त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों के खिलाफ अब पूरा अखाड़ा परिषद मुखर हो उठा है। जरूरत है ऐसे ही अन्य शीर्ष धर्म संगठनों के सक्रिय होकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाई करने की।

फर्जी एवं पाखण्डी बाबाओं के मामले में भोले-भाले एवं अशिक्षित लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और जिन बाबाओं ने ये कुकर्म किया है, उन्हें ढूंढकर दंड देना ही चाहिए। फर्जी एवं पाखण्डी बाबाओं की परंपरा सदैव से दुष्टों के हाथ में रही है। इसका आरंभ किया था महाभारत में शकुनि ने। हमारे समाज एवं राष्ट्र ऐसे बहुत सारे बाबा रूपी शकुनि हैं, जिन्हें हम समय पर पहचान नहीं पाते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच जब जुए का खेल हुआ, तो शर्त यही थी कि पांसे शकुनि चलेगा। शकुनि ने पांसे भी ऐसे तैयार किए थे कि उसको परिणाम और प्रश्न मालूम थे। आधुनिक बाबा भी ऐसे ही पांसे चलते हुए हुए कइयों की जिंदगी को नरक बना रहे हैं, कइयों के घर उजाड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है, जो धार्मिक आस्थाओं के प्रति अटूट विश्वास रखते थे, क्योंकि भारत की पहचान सदा से ही साधु-संतों से जुड़ी रही है। लेकिन पिछले एक-दो दशक से कुछ फर्जी बाबाओं ने अपनी काम वासना एवं धनलोलुपता के चलते सबकुछ खंडित कर दिया है। इन बाबा रूपी शकुनियों को दंड देना ही पड़ेगा। आधुनिक बाबाओं की तरह महाभारत का शकुनि कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन वो कहता था, दुर्योधन! मैं इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति से डरता हूं और वो श्रीकृष्ण हैं। तो हमें भी आधुनिक बाबाओं के लिये श्रीकृष्ण जैसी एक सख्त व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि श्रीकृष्ण जब किसी को दंड देते थे तो अपना और पराया कभी नहीं देखते थे। श्रीकृष्ण धर्म में जय और जय में धर्म देखते थे। वर्तमान में धर्मगुरुओं एवं बाबाओं का जो चरित्र एवं आचरण प्रस्तुत हो रहा है, वह कष्टदायक एवं विनाशकारी है। इसलिये उनके लिये श्रीकृष्ण रूपी अनुशासन-व्यवस्था को सख्ती से लागू करना ही होगा।

अखाड़ा परिषद का अपना अनुशासन है। अखाड़े से जुड़े संतों में कोई दोष नहीं आ जाए, चरित्रहीनता न आ जाये, आचरण एवं जीवनशैली दूषित न हो जाये, इसे देखते हुए वह समय-समय पर अपने महामण्डलेश्वर व दूसरे संतों की कार्यप्रणाली की गोपनीय जांच कराता रहता है। ऐसी ही हाल में की गयी जांच में सामने आया कि धनार्जन में लिप्त रहने वाले संतों की कार्यप्रणाली अखाड़ों की रीति-नीति के विपरीत थी। इनमें कुछ के तो आपराधिक लोगों से भी संबंध सामने आए। राजनेताओं से भी उनके प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। हर समुदाय में संतों का अलग ही स्थान रहता आया है। वे जहां विराजते हैं वह स्थान स्वतः ही उच्च हो जाता है। आज भी बड़ी संख्या में संत-महात्मा समाज को दिशा देने के काम में निःस्वार्थ भाव से जुटे हैं। पर बदलते दौर में संत-महात्मा-मुल्ला-मौलवियों व पीर-पगारों के छद्म-पाखण्डी वेश में ऐसे लोग भी सामने आने लगे हैं जो धार्मिक कार्यकलापों की बजाय न केवल अर्थार्जन में जुटे रहते हैं बल्कि अंधविश्वास, व्यभिचार और पाखण्ड को बढ़ावा देने में जुटे हैं। छद्म धर्मगुरु और संत लोगों की धार्मिक श्रद्धा एवं अंधभक्ति का फायदा उठाकर उन्हें ठगते हैं। ऐसे लोगों का गाहे-बगाहे सियासी जुड़ाव भी सामने आता रहता है। ऐसे ही लोग संत समाज को बदनाम करते हैं, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था भी डगमगाने लगती है।

धर्मगुरुओं के धन के प्रति बढ़ते आकर्षण ने भी अनेक तरह की विसंगतियों एवं विकृतियों को जन्म दिया है। अब तक धर्म और धर्मगुरुओं के इर्द-गिर्द ठाट-बाट और राजा-महाराजाओं जैसी वैभवपूर्ण स्थितियां ही देखने को मिलती थीं, लेकिन अब ये तथाकथित धर्मगुरु स्वयं व्यापारी बनकर बड़ी-बड़ी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। एक प्रमुख महिला धर्मगुरु बहुत सारे धार्मिक कार्यों के अलावा अस्पताल, एक टीवी चैनल, इंजीनियरिंग कॉलेज और बिजनेस स्कूल चलाती है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए विश्व धार्मिक सांस्कृतिक सम्मेलन में देखा कि किस तरह से पानी से लेकर खाद्य पदार्थ तक बेचे गए। एक बड़ा पंथ चलाने वाले राम-रहीम ऑर्गेनिक उत्पाद खिलाकर देश को सेहतमंद बनाने की तमन्ना रखते हैं। ये एक ऐसी लंबी सूची है जिसमें वर्तमान के लगभग सभी चर्चित धर्मगुरु ऐसे ही व्यावसायिक कार्यों और लाभकारी इकाइयों से जुड़े हैं। व्यावसायिक लाभों के लिए राजनीतिक और व्यावसायिक नेटवर्क रखने के साथ-साथ बड़ी संख्या में धार्मिक अनुयायी रखना इन तथाकथित धर्मगुरुओं की परंपरा रही है।

राजनीति पर धर्म के अनुशासन की बात उचित है, लेकिन धर्मगुरुओं को प्रतिष्ठापित करने के बहाने राजनीति का खेल न खेला जाए, इस बात की जरूरत सर्वाधिक है। अपनी लोकप्रियता के बल पर कुछ धर्मगुरु भारतीय राजनीति के बदलते दौर में कुछ सीटें जीतकर सामने आए हैं। धर्मगुरु से राजनीतिज्ञ बन जाने की ये घटनाएं न केवल धर्मक्षेत्र के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी घातक हैं। जहां धर्मगुरुओं के अनुयायी अधिक संख्या में हैं, उन क्षेत्रों में वे स्वयं जीतें न जीतें, वहां के परिणाम को प्रभावित कर ही सकते हैं। उनका यह असर किस दिशा में होगा? कौन सी बड़ी ताकत को लाभ मिलेगा? यानी राजनीति एवं राजनेताओं पर इन धर्मगुरुओं एवं बाबाओं का गहरा प्रभाव एवं वर्चस्व भी अनेक विसंगतियों का कारण बना है। हाथरस में सूरजपाल जाटव उर्फ साकार हरि 'बाबा' के तथाकथित सत्संग में 121 लोगों की मौत का कारण बना। ऐसे फर्जी एवं तथाकथित चमत्कारी बाबाओं के चक्कर लगाने वालों में महिलाएं एवं दलित बड़ी संख्या में हैं। भगदड़ एवं अन्य हादसों की स्थिति में यही लोग मारे जाते हैं। प्रश्न है कि ढोंगी एवं पाखण्डी बाबाओं के पास जाने वाले लोग अपनी तर्क-बुद्धि एवं विवेक से काम क्यों नहीं लेते? अंधविश्वासों के सहारे तरक्की की सीढ़ियां क्यों चढ़ना चाहते हैं? ये विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं। जनता की कमजोरी के कारण ही कभी हमारे यहां धर्म की राजनीति में घुसपैठ होती रही है तो अब आर्थिक गतिविधियों से उनका गठबंधन हो रहा है। जब-जब ऐसी स्थितियां हुई हैं, तब-तब धर्म और धर्मगुरु अपने विशुद्ध स्थान से खिसके हैं। खिसकते-खिसकते वे ऐसी डांवाडोल स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां धर्म को अफीम कहा जाने लगा है। (लेखक-ललित गर्ग/ ईएमएस)

किसान आन्दोलन की समाधान राहें बातचीत से ही खुलेगी

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, एक बार फिर किसान आन्दोलन के उग्र से उग्रतर होने की संभावनाएं हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसान-आन्दोलन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का औचित्यपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। प्रश्न है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल न्यायालय के इस महत्वपूर्ण सुझाव को आकार देने की बजाय किसान-आन्दोलन को उग्र करने की मंशा रखते हुए अराजक माहौल ही क्यों बनाना चाहते है? क्यों अव्यवस्था फैलाने चाहते हैं? निश्चित ही शंभू बॉर्डर खोले जाने पर कानून-व्यवस्था को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बात सही है कि शंभू बॉर्डर खोले जाने से आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच की राह खुल सकती है। आंदोलनरत किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी सीमाएं खुलेंगी, किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति के जरिए बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन दोनों पक्षों को ही आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकालने की पहल करनी होगी। किसान आंदोलन के उग्र रूप को भी यह देश देख चुका है, भारी नुकसान भी हुआ है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं और इनकी आड़ में होने वाली राजनीति अपनी जगह। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर समिति के गठन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार पहले ही दे चुकी है। यह बड़ा सच है कि बात करने से ही बात बनती है। बातचीत की हर संभावना का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन का लंबे वक्त तक जारी रहना सचमुच चिंताजनक है। ऐसे आन्दोलन को उग्र करने की विपक्षी दलों की मानसिकता भी संदेहों एवं अविश्वासों से घिरी है। अच्छा हो कि विपक्षी दल एवं नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट में कृषि क्षेत्र के लिये किये गये बड़े ऐलानों पर गौर करें। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मौसम में बदलाव को बरदाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट को भी बढ़ाया गया है।

विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों एवं कृषि को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। कोई न कोई बहाना चाहिए विरोध का, अब किसान-आन्दोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में देश का कितना नुकसान होगा, कहा नहीं जा सकता। जबकि भाजपा सरकार द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि में उत्पादकता, किसानों के हितों एवं कृषि की सुदृढ़ता को बढ़ाना बजट द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि बजट में जो नौ प्राथमिकताएं शामिल है, उनमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति शृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को बर्बाद होने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। भले ही सरकार ने सीधे तौर पर बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित न किए जाने से किसानों को निराशा हुई हो लेकिन बजट में तिलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन केन्द्र विकसित करने और खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी जो सीधे तौर पर किसानों की आय भी बढ़ायेगा एवं उन्नत कृषि को प्रोत्साहन भी देगा।

असल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगें राजनीतिक मुद्दे बन गये हैं, जिनके चलते हो रहा आन्दोलन न केवल किसानों के बल्कि आम जनता के लिये भी परेशानी का सबब है। जबकि सरकार ने धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ा कर 2300 कर दिया है जो स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद थी की सरकार एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी। लेकिन बजट में इस तरह का कोई प्रावधान न होने से काफी निराशा हुई है। दुनिया भर के विकसित देश अनिवार्य रूप से किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदते हैं। लेकिन भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। विपक्षी दल किसानों के हित में आन्दोलन की बजाय बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े। स्तरीय विरोध हो, किसानों को गुमराह करने एवं उनका मनोबल कमजोर करने के लिये विपक्षी दल उजालों पर कालिख न पोते, इससे उन्हीं के हाथ काले होने की संभावनाएं है। (लेखक-ललित गर्ग/ ईएमएस)

अगर यह सुशासन है तो जंगल राज क्या है ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी संभालने के जब डॉ.मोहन यादव ने यह कहना शुरू किया था कि राज्य में क़ानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा उस समय प्रदेशवासियों में यह उम्मीद जगी थी कि प्रदेश को मिला नया नेतृत्व शायद राज्य से भय,आतंक व अराजकता के वातावरण को दुरुस्त कर सकेगा । परन्तु राज्य के हालात क़ानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक अभी भी न केवल जस के तस बने हुये हैं बल्कि अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली कुछ घटनाओं से तो ऐसा प्रतीत होने लगा है गोया सत्ता बदलने या मुख्यमंत्री की क़ानून व्यवस्था सम्बन्धी किसी चेतावनी का अपराधियों पर कोई असर ही नहीं। हद तो यह है कि प्रदेश में घटी अनेक बड़ी आपराधिक घटनाओं में सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों के शामिल होने के भी प्रमाण मिलते रहे हैं। तभी विपक्ष को भी पूछना पड़ रहा है कि प्रदेश में होने वाली हर बड़ी आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े लोग शामिल होते पाए गए हैं। तो क्या सरकार और पार्टी इस दिशा में कोई क़दम उठाने वाली है? विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को जंगलराज के टैग से मुक्ति कब मिलेगी ? और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचार कब समाप्त होंगे ?

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में इलाहबाद मार्ग पर स्थित मंगावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबंगों द्वारा अपनी दबंगई का वह प्रदर्शन किया गया जो शायद आजतक उस बिहार व उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में भी नहीं हुआ जहाँ लालू यादव व अखिलेश यादव के राज को जंगल राज कहकर यही सत्ताधारी भाजपाई आज भी सम्बोधित किया करते हैं। रीवा ज़िले के हिनौता क्षेत्र में हुई इस घटना में गुंडों ने डंपर से बजरी फेंककर दो महिलाओं को ज़िंदा दफ़नाने की कोशिश की। इस घटना में ममता पांडे और आशा पांडे नाम की दो महिलाएं बजरी के ढेर में कमर और गर्दन तक दब गई थीं। जिन्हें स्थानीय लोगों ने फावड़े की सहायता से बजरी के ढेर में से बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई। इन महिलाओं को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यदि स्थानीय लोग मानवता का प्रदर्शन करते हुये उन महिलाओं को समय रहते बजरी के ढेर से बाहर न निकालते तो दोनों महिलाएं ज़िंदा ही दफ़्न हो जातीं। बताया जा रहा है कि इस गांव में एक सड़क निर्माण योजना को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। उन महिलाओं का दावा है कि चूँकि यह ज़मीन उन्हें सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थी इसीलिये वे उस ज़मीन पर सड़क निर्माण का विरोध कर रही थीं। और जब उन्होंने सड़क निर्माण रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित महिलाओं ने गौकरण प्रसाद पांडे, महेंद्र प्रसाद पांडे सहित अन्य कई व्यक्तियों पर हमला करने और डंपर चालक पर उन्हें ज़िंदा दफ़नाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

मोहन यादव सरकार से पहले शिवराज चौहान सरकार में भी इस राज्य में मानवता को शर्मसार करने वाली दबंगई की कई शर्मनाक घटनायें हो चुकी हैं। गत वर्ष जुलाई माह में मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बिकौरा गांव में पंचायत के लिए नाली का निर्माण कार्य चल रहा था।उस समय रामकृपाल पटेल नामक व्यक्ति पास के एक हैंडपंप पर नहा रहा था। बताया जाता है कि उसी समय दलित समुदाय के एक व्यक्ति दशरथ अहिरवार ने हंसी मज़ाक़ के माहौल में ग्रीस लगे हाथ से आरोपी रामकृपाल पटेल को छू लिया। तभी ग़ुस्साया पटेल नहाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मग में पास में पड़ा मानव मल भर लाया और इसे दशरथ अहिरवार के सिर और चेहरे सहित पूरे शरीर पर भी लगा दिया। पीड़ित दलित दशरथ अहिरवार ने यह भी आरोप लगाया कि पटेल ने इस दौरान उसे जाति के आधार पर अपमानित भी किया। और जब उसने मामले की सूचना पंचायत को दी और बैठक बुलाई। तो पंचायत ने उल्टे उसी पर 600 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।

यह वही मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ गत वर्ष जुलाई में सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत प्रवेश शुक्ला नामक एक युवक ने एक आदिवासी युवक के मुंह व चेहरे पर पेशाब करते अपनी वीडियो बनवाई थी। बाद में आरोपी प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध बहारी थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (अश्लील हरकतें), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आरोपी के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी शुरू की गई थी। मानवता को आहात करने वाली इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया था। इस घटना की वीडिओ भी वायरल हुई थी। इस घटना का ज़िक्र विदेशी मीडिया ने भी किया था। वैसे भी मध्य प्रदेश पूरे देश में दलितों के साथ अपराध के मामलों में तीसरे स्थान पर है। विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को जंगलराज के टैग से मुक्ति कब मिलेगी ?

एक दो दशक पहले के ख़ासकर उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्य दलों के शासन को आज भी गुंडा राज कहकर याद करने वाली भाजपा के शासन में आख़िर कौन सा अपराध नहीं हो रहा है ? पुलिस कस्टडी में लोगों की संदिग्ध अवस्था में हत्यायें हो जाना क्या अराजकता की निशानी नहीं ? गैंग रेप, अपहरण दलितों व अल्पसंख्यकों पर ज़ुल्म क्या यह बेहतर क़ानून व्यवस्था के लक्षण हैं ? जेल में गैंगवार और हत्यायें बेहतर क़ानून व्यवस्था की परिचायक तो हरगिज़ नहीं? दरअसल भाजपा नेताओं व सरकार की प्राथमिकतायें कुछ और ही हैं। छोटे मोटे अपराधों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों के घरों व व्यवसायिक ठिकानों पर बुलडोज़र चलाकर दूसरे समुदाय के लोगों की वाहवाही लूटना यानी एक की बर्बादी दिखाकर दूसरों को ख़ुश करना यही इनकी लोकप्रियता का शार्ट कट है। अन्यथा डंपर से बजरी फ़ेंक कर दो महिलाओं को ज़िंदा दफ़्न करने से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है ? देश के तमाम मीडिया ने इस घटना को तालिबानी कृत्य का नाम दिया। यहाँ आख़िर बुलडोज़र क्यों नहीं चला ? यदि इस तरह के दुस्साहसिक गुंडा राज के दौर को भी सुशासन बताने की कोशिश की जाये फिर आख़िर जंगल राज किसे कहा जाये ? (लेखिका - निर्मल रानी/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8080

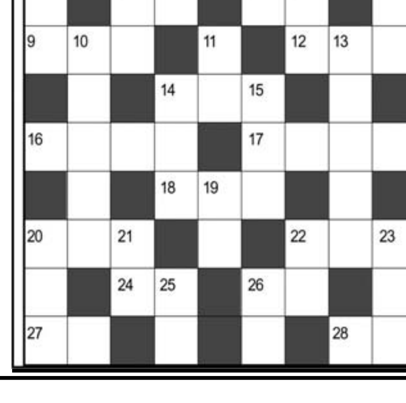

बाएँ से दाएँ

1. उचित, गलत का विलोम-2
4. अधिकार-2
6. परछाई-2
7. सम्मान, प्रसिद्धि-2
9. उल्टी, कै, वमन-3
12. रंग (अंग्रेजी-3)
14. चंचल, फुर्तीला-3
16. भयभीत होना-4
17. फुर्तीलापन-4
18. बसंत काल-3
20. भ्रम, वहम-3
22. आश्रय, शरण-3
24. राजनीतिक पार्टी-2
26. शारीरिक ऊंचाई-2
27. गन्ना-2
28. शाखा, टहनी-2

ऊपर से नीचे

1. नमस्ते, आदाब-3
2. देह, बदन, तन-2
3. शराब, मदिरा-2
5. डोली उठानेवाले-3
6. पत्नी की छोटी बहन -2
8. वहम, संदेह-2
10. जरुरतमंद-5
11. नाग, सर्प-2
13. आनंदित होना -5
14. भारत से निकलने वाली नदी जो पाकिस्तान में खत्म होती है-3
15. ढीला, सुस्त-3
19. नुकसान, घाटा-2
20. सद्कार्य-3
21. नशा, सरुर, खुमार-2
22. ओहदा -2
23. भवन, कोठी-3
25. क्षण, पल-2
26. कलिका, फूल खिलने से पहले की स्थिति-2

शब्द पहेली -8079 का हल

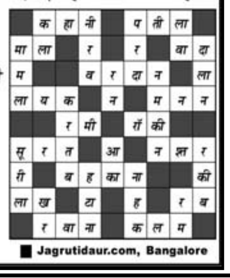

Jagrutidaur.com, Bangalore

सम्पादकीय

खेल-समाचार

सूर्यकुमार और गंभीर करेंगे अपनी नई पारी की शुरुआत

पल्लेकेले (ईएमएस)। भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार से यहां शुरु हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज से नये कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव एकसाथ मिलकर अपने काम-काज की शुरुआत करेंगे। इस दौरे में इन दोनो की पहली परीक्ष होगी क्योंकि कई युवा खिलाड़ियों के साथ उतर रही है। । भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। टीम चयन में गंभीर को पूरी आजादी मिली और ऐसे में टीम को जीत दिलाना उनका लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा इस सीरीज से सूर्या के कप्तानी कौशल का भी पता चलेगा।

रोहित शर्मा, जो अब टी20 से संन्यास ले चुके हैं। टी20 के बाद होने वाली तीन मैचों की वनडे वहीं श्रीलंका में भी सबसे छोटे प्रारूप में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें वनिन्दु हसरंगा की जगह चरिथ असालंका को कप्तान बनाया जाएगा जबकि क्रिस सिल्वरवुड की जगह सनत जयसूर्या अंतरिम मुख्य कोच बनाये गये हैं।

सूर्यकुमार टी20 प्रारुप में विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में शामिल हैं। अब देखना होगा कि वो कप्तानी के बाद अपने खेल में क्या बदलाव करते हैं। वहीं गंभीर के लिए यह एक अच्छी शुरुआत करने का मौका है।

भारत के मुरली को पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान मिला

पेरिस (ईएमएस)। भारत के मुरली श्रीशंकर ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पेरिस डायमंड लीग तीसरा स्थान हासिल किया है। मुरली ने पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.09 मीटर की छलांगे लगायी और वह तीसरे स्थान पर रहे। मुरली ने अपने तीसरे प्रयास में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। 8.09 वह वहीं यूनान के मिल्टियाडिस टेंटोग्लू ने 8.13 मीटर की छलांग के साथ पेरिस डायमंड लीग जीती।

स्विट्जरलैंड के साइमन एहमर द्वारा 8.11 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया जबकि मुरली तीसरे स्थान पर खिसक गये। मुरली के पांचवें प्रयास में 7.99 मीटर की छलांग लगायी पर उनक प्रयास फाउल के साथ खत्म हुआ।

डायमंड लीग में श्रीशंकर की यह दूसरी उपस्थिति थी। पिछले साल मोनाको में वह 7.94 मीटर की छलांग लगाकर छठे स्थान पर रहे थे। उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग 8.36 मीटर है जो उन्होंने पिछले साल लगाई थी। श्रीशंकर लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतकर डायमंड लीग के पेरिस चरण में पहुंचे। उन्होंने पिछले महीने ही यूनान के कालिथिया में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर का कांस्य पदक जीता था, जिसमें उन्होंने सीजन की अपनी सर्वश्रेष्ठ 8.18 मीटर की छलांग लगाई थी और चीन में होने वाले आगामी एशियाई खेलों के लिए कट हासिल किया था। पेरिस में डायमंड लीग की वार्षिक श्रृंखला का चौथा चरण था।

जोकोविच, नडाल और अल्काराज पेरिस ओलंपिक में शनिवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक में सर्सियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के अलावा स्पेन के राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज यहां प्रतियोगित के पहले ही दिन शनिवार को अपने-अपने मुकाबले खेलेंगे। जोकोविच जहां पुरुष एकल में मैथ्यू एबडेन का सामना करेंगे। वहीं नडाल युगल में और अल्काराज दोनों में ही प्रतिस्पर्धा करेंगे। नडाल और अल्काराज पुरुष युगल टीम में जोड़ीदार हैं। इस जोड़ी का पहला मुकाबला अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रेस मोल्टेनी से होगा। नडाल एकल में अपना पहला मैच हंगरी के मार्टन फुकसोविक्स से खेलेंगे। अगर वह यह मैच जीत जाते हैं और जोकोविच एबडेन को हरा देते हैं तो फिर यह दोनों दिग्गज खिलाड़ी दूसरे दौर में मुकाबला करेंगे।

नडाल ने 2008 में एकल और 2016 में युगल में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था पर जोकोविच अभी तक ओलंपिक विजेता नहीं बन पाए हैं। अपने करियर में रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम जीतने वाले और बीजिंग ओलंपिक 2008 के कांस्य पदक विजेता जोकोविच ने कहा, 'ओलंपिक से बहुत सारी उम्मीदें हैं तथा मैं इसे नहीं बदल सकता और मैं इसे बदलना भी नहीं चाहता हूं। इनसे मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलती है।

आयरलैंड के साथ मुकाबले में 210 रनों पर सिमटी जिम्बाब्वे

बेलफास्ट (ईएमएस)। आयरलैंड के साथ यहां जारी टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे की टीम मुश्किलों में घर गयी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे पहली पारी में 210 रनों पर ही सिमट गयी। इस मैच में एक समय जिम्बाब्वे ने 4 विकेट पर 193 रन बना लिए थे पर इसके बाद उसने एकदम से छह विकेट खो दिये। शुरुआत में लगा कि जिम्बाब्वे 350 या फिर 400 रन का स्कोर खड़ा कर सकता है पर बाद में हालात बदल गये। .

जिम्बाब्वे ने अपने अंतिम 6 विकेट 17 रन पर खो दिये। जिम्बाब्वे की ओर से इस मैच में सबसे अधिक 74 रन सलामी बल्लेबाज प्रिंस मसवारे ने बनाए। उन्होंने 74 रन की पारी खेली। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज जॉयलॉर्ड गुम्बी ने 49 रन बनाए। सॉन विलियम्स ने 35 रन बनाये। आयरलैंड की ओर से बैरी मैक्कार्थी और एंडी मैकब्राइन ने 3-3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे की ओर से इस मैच में सलामी बल्लेबाज जॉयलॉर्ड के अलावा ब्रायन बेनेट और क्लाइव मडांडे ने डेब्यू किया। जॉयलॉर्ड अपने डेब्यू मैच में भी अर्धशतक नहीं लगा पाये।

इस माह के अंत में होगी बीसीसीआई और आईपाएल टीमों की बैठक ,कई मामलों पर होगी बात

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और टीम मालिकों की एक बैठक इस माह के अंत में होगी। इससे आईपीएल फ्रैंचाइजी अपनी मांग बोर्ड के सामने रखेंगे। इससे फ्रैंचाइजी कितने खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। इस बार में पूछेंगे और ये संख्या बढ़ाने की मांग करेंगे। इसके अलावा आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी से पहले राइट टू मैच (आरटीएम) को लेकर भी बात करेंगे।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएल के मुख्य कार्यकारी हेमांग अमीन ने 31 जुलाई को होने वाली इस बैठक के लिए सभी फ्रेंचाइजी मालिकों को संदेश भेजकर उन्हें इसमें शामिल होने कहा है। बैठक 31 जुलाई को दोपहर या शाम को होगी। वहीं ऐसी रिपोर्ट है कि सभी मालिकों ने बैठक के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है। राइट टू मैच विकल्प को लेकर विवाद है जिसका हल इस बैठक में निकल सकता है।

हालांकि अभी स्थल की पुष्टि नहीं हुई है पर ये बैठक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम परिसर में स्थित बीसीसीआई मुख्यालय क्रिकेट सेंटर में होगी। आईपीएल 2018 बड़ी नीलामी से तीन और अन्य राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करके फ्रेंचाइजी को अधिकतम पांच खिलाड़ियों को बनाए रखने की अनुमति थी पर 2022 में दो नई टीमों गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरूआत के बाद टीमों को चार खिलाड़ियों को बनाए रखने की अनुमति दी गई, जिसमें कोई आरटीम कार्ड शामिल नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीसीसीआई द्वारा रिटेंशन की संख्या बढ़ाकर पांच या छह की जा सकती है।

रिटेंशन को सीमित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि इससे अधिक संख्या नीलामी के उत्साह को घटा कर सकती है। य

पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक में इसबार भारतीय पुरुष हॉकी टीम का लक्ष्य अपने पदक का रंग बेहतर करना होगा। इसमें भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला शनिवार को होगा। भारतीय हॉकी टीम इन खेलों में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में उतरेगी। भारतीय टीम ने पिछले ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ऐसे में इस बार उससे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। टीम में इस बार अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। भारतीय दल में पीआर श्रीजेष और मनप्रीत सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस साल अपने चौथे ओलंपिक में भाग लेंगे। श्रीजेष गोलकीपर के साथ ही भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। भारतीय टीम को यहां दूसरे ग्रुप में रखा गया है। 12 टीमें दो ग्रुप में बांटी गई हैं, हर ग्रुप में 6 टीमें होंगी।हर टीम दूसरी पांच टीमों के खिलाफ एक बार खेलेगी।

ग्रुप इस प्रकार हैं:

ग्रुप एः नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका ग्रुप बीः बेल्जियम, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, आयरलैंड भारतीय हॉकी टीम का कार्यक्रम इस प्रकार है। भारत और न्यूजीलैंड – 27 जुलाई (रात 9 बजे आईएसटी) भारत और अर्जेंटीना – 29 जुलाई (दोपहर 4:15 बजे आईएसटी) भारत और आयरलैंड – 30 जुलाई (दोपहर 4:45 बजे आईएसटी) भारत और बेल्जियम – 1 अगस्त (दोपहर 1:30 बजे आईएसटी) भारत और ऑस्ट्रेलिया – 2 अगस्त (दोपहर 4:45 बजे आईएसटी) पेरिस ओलंपिक हॉकी प्रारुप

सूर्यकुमार की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ जीत से शुरुआत करने उतरेगी भारतीय टीम

पालेकल (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को नये कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम इस दौरे में श्रीलंका से तीन मैच खेलेगी और गंभीर व सूर्या की जोड़ी का लक्ष्य इसमें टीम को जीत दिलाना रहेगा।

गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह कोच बनाया गया है। गंभीर को अब उनके काम को आगे बढ़ाना होगा। गंभीर को इस दौरे में उनकी मांग के अनुसार टीम दी गयी है। ऐसे में उनकी पहली परीक्षा ये दौरा होगा। इस दौर में सूर्यकुमार को कप्तान बनाया गया है जबकि हार्दिक पंडया इस पद के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे। इसके अलावा कई युवा खिलाड़ियों को भी अवसर मिला है।

भारतीय टीम में यह बदलाव पिछले महीने विश्व कप जीतने तथा रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आया है। इस सीरीज में उपकप्तानी संभाल रहे शुभमन गिल इसे अपनी जगह पक्की करने के अवसर के रूप में देखेंगे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और यहां तक कि रियान पराग जैसे अन्य खिलाड़ी भी यही चाहेंगे। अक्षर पटेल टीम में जडेजा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके अलावा भारत के पास हार्दिक, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।

इस दौरे में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और ऐसे में गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज पर रहेगी। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शुभमन , सूर्यकुमार जैसे बल्लेबाजों पर रहेगी। वहीं दूसरी ओर मेजबान श्रीलंकाई टीम की राह भी आसान नहीं है। उसके दो अनुभवी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गये हैं। अब उनकी जगह असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका को टीम में लिया गया है।

श्रीलंकाई टीम इस सीरीज में नये कतान चरिथ असलांका और अंतरिम कोच सनत जयसूर्या के मार्गदर्शन में उतरेगी। मेजबान टीम घरेलू हालातों का लाभ उठाकर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। उसके पास दासुन शनाका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ियों के पास रहेगी।

मॉस्को में कार बम विस्फोट करने वाला संदिग्ध तुर्की में गिरफ्तार

मॉस्को,(ईएमएस)। मॉस्को कार बम विस्फोट मामले में संदिग्ध येवगेनी सेरेब्रीकोव को तुर्की में गिरफ्तार किया गया और उसे रूस भेज दिया गया है। यह जानकारी रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) के जनसंपर्क विभाग ने शुक्रवार को मीडिया को दी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार सुबह उत्तरी मॉस्को के सिन्याविंस्काया स्ट्रीट पर एक घर के आंगन में कार में विस्फोट हो गया था जिसमें दो लोग घायल हो गए थे। रूसी मंत्रालय के मुताबिक कार में रखी एक अज्ञात वस्तु में विस्फोट हुआ था। मॉस्को की ज़मोस्कोर्वोत्स्की कोर्ट ने स्पुतनिक से कहा कि उसने सेरेब्रीकोव को उसकी अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया था।

एफएसबी ने जारी बयान में कहा कि रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने रूसी आंतरिक मंत्रालय के साथ और तुर्की के विशेष बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से, संदिग्ध को तुर्की के शहर बोडरम से हिरासत में लिया गया । बताया जा रहा है रूसी नागरिक येवगेनी सेरेब्रीकोव, जिनका जन्म 1995 में हुआ था, जो कि अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में हैं। 24 जुलाई को उत्तरी मास्को में एक कार बम विस्फोट में शामिल था। बयान में कहा गया कि एफएसबी अधिकारियों ने संदिग्ध को हत्या के प्रयास और विस्फोटक या विस्फोटक उपकरणों के अवैध अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण, परिवहन करने के लिए जांचकर्ताओं को सौंप दिया है।

29 जुलाई का महत्वपूर्ण दिन.......जब तय होगी यूपी की राजनीतिक दिशा

लखनऊ (ईएमएस)। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबर्दस्त हलचल मची हुई है। बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी ने इनदिनों सुर्खियाँ बटोरी हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब मुखर हो चुके हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। इस बीच, सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ को छोड़कर दिल्ली का रुख किया है। इस बदलती स्थिति ने 29 जुलाई को यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया है।

29 जुलाई को यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और इसी दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अखिलेश ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी इसी दिन होना है। सीएम योगी के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को सुलझाते हुए सहयोगी दलों का विश्वास भी प्राप्त करना होगा। सपा ने लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया है, जिससे उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ है। इस विजय के बाद सपा विधानसभा में भी आक्रामक रुख अपनाने की योजना बना रही है। कांग्रेस का समर्थन भी उनकी स्थिति को मजबूत करता है। विपक्षी दलों के मुद्दों का सामना करना बीजेपी के लिए कठिन हो सकता है, खासकर जब मुद्दे बिजली कटौती, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर नेम प्लेट विवाद और ओबीसी आरक्षण जैसे प्रमुख विषयों पर हो। बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी अभी कशमकश में हैं।

उधर, राज्यपाल आनंदीबेन का कार्यकाल 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसी दिन विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होगी, और नए राज्यपाल की नियुक्ति या कार्यकाल का विस्तार इसी दिन से पहले पूरा करना होगा। यूपी के इतिहास में किसी भी राज्यपाल को लगातार दो कार्यकाल नहीं मिले हैं, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आनंदीबेन पटेल को केंद्र की मोदी सरकार विस्तार देती है या नया राज्यपाल नियुक्त करती है। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीतने के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। शिवपाल सिंह यादव, इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर जैसे नाम इस पद के लिए सामने आ रहे हैं। 29 जुलाई का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो प्रदेश की राजनीतिक दिशा और संभावनाओं को आकार देगा।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आये उछाल से आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,292.92 अंक करीब 1.62 फीसदी ऊपर आकर 81,332.72 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 428.75 अंक तकरीबन 1.76 फीसदी बढ़कर 24,834.85 के शीर्ष स्तर पर बंद हुआ।

आज के कारोबार में सेंसेक्स के 29 शेयर लाभ पर बंद हुए। भारती एयरटेल, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और इंफोसिस सेंसेक्स के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। भारती एयरटेल 4.51 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रही। इसके अलावा सन फार्मा, एचसीएल टेक, एमएंडएम, आईटीसी, टाटा मोटर्स, टाइटन, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनैंस, एसबीआई, इंडसइंड, एशियन पेंट्स, टीसीएस, पावर ग्रिड, एलएंडटी, मारुति, रिलायंस, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचयूएल और एचडीएसफसी बैंक के शेयर भी लाभ में रहे।

वहीं, दूसरी तरफ सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल एक शेयर ही नुकसान पर बंद हुआ। ये शेयर नेस्ले इंडिया का था। इसमें 0.07 फीसदी की हल्की गिरावट रही।

वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में, सियोल, शंघाई और हांगकांग ऊपर आये जबकि टोक्यो में गिरावट रही। यूरोपीय बाजार भी ऊपर आया है। गत दिवस अमेरिकी बाजार में गिरावट रही।

अल्जीरिया में तीन उम्मीदवार योग्य घोषित

अल्जीयर्स,(ईएमएस)। अल्जीरिया के नेशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर इलेक्शन (एएनआईई) ने देश में सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीन लोगों की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एएनआईई के प्रमुख मोहम्मद चोर्फी ने सितंबर में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एएनआईई ने राष्ट्रपति अब्देलमदजीद तेब्बौने, सोशलिस्ट फोर्सेज फ्रंट के महासचिव यूसेफ औचिचे और मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर पीस के प्रमुख अब्देलअली हसनी चेरीफ की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी गई है और उन्हें योग्य माना है क्योंकि वे निर्धारित सभी जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अल्जीरिया के चुनावी कानून के मुताबिक चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी उम्मीदवार को नगरपालिका, प्रांतीय या संसदीय परिषदों के चुने गए सदस्यों से 600 लोगों के हस्ताक्षर लेने होते हैं या कम से कम 29 प्रांतों में पात्र मतदाताओं में से कम से कम पचार हजार हस्ताक्षर लेने होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रांत से कम से कम बारह सौ हस्ताक्षर शामिल हैं। राष्ट्रपति तेब्बौने ने 21 मार्च को तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए सात सितंबर को मध्यावधि राष्ट्रपति चुनाव कराने का फैसला लिया था। उन्होंने 11 जुलाई को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था।

भारत करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी

वाशिंगटन(ईएमएस)। इस साल भारत क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की उपस्थिति को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस साल भारत में होने वाले क्वाड देशों के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध हैं। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है।

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकारजॉन किर्बी ने कहा, हम इस साल होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी फिलहाल कैलेंडर में इसे लेकर कुछ भी तय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो बाइडन अब राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि कैलेंडर पर ऐसे अवसर होंगे जो पहले नहीं थे। किर्बी ने कहा, हम सभी के दिमाग में यह बात है कि उनकी विदेश नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा के अवसरों के मामले में वे मौके क्या हो सकते हैं? लेकिन मेरे पास अभी बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि देखते रहिए, समय आने पर सब पता चल जाएगा।

सोना 500 रुपए बढ़ कर 67,850, चांदी 81,400 रुपए

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने-चांदी के वायदा भाव में गुरुवार को बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार को सुधार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 67,850 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 81,400 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने व चांदी के वायदा भाव में तेजी देखी जा रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 528 रुपये की तेजी के साथ 67,990 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 387 रुपये की तेजी के साथ 67,849 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत आज तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 331 रुपये की तेजी के साथ 81,662 रुपये पर खुला। इस समय यह 69 रुपये की तेजी के साथ 81,400 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,363.80 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,353.50 डॉलर प्रति औंस था। ?फिलहाल यह 18.80 डॉलर की तेजी के साथ 2,372.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 27.99 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 27.97 था। ?फिलहाल यह 0.04 डॉलर की तेजी के साथ 28.01 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

बजट के बाद कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत घटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट पेश होने के बाद कई चीजों के दाम में बदलाव देखने को मिला है। वहीं बजट के बाद कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भी कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हुए हैं। हालांकि कीमतों में बदलाव आंशिक है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी आई है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि महाराष्ट्र में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपए प्रति लीटर है। बिहार में पेट्रोल 3 पैसे घटकर 107.09 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 पैसे घटकर 93.81 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। यूपी में पेट्रोल 10 पैसे घटकर 94.39 रुपए प्रति लीटर और डीजल 11 पैसे घटकर 87.44 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है। यहां पेट्रोल 1 रुपए 22 पैसे बढ़कर 105.09 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए 17 पैसे घटकर 91.59 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

उत्तरी जापान में बाढ़ व भूस्खलन से सैकड़ों लोग बेघर, शरण लेने को मजबूर

टोक्यो,(ईएमएस)। देश ही नहीं इस बार बारिश ने कई दशों में तबाही मचा रखी है। उत्तरी जापान में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से आवागमन बाधित हो गया है और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जापान मौसम विभाग ने यामागाटा और अकिता प्रांत के कई शहरों के लिए चेतावनी जारी की है। इन शहरों में अब तक गर्म हवाएं चलने के कारण उमस से लोग परेशान थे। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने प्रभावित इलाकों के लोगों से मौसम संबंधी जानकारियों पर लगातार नजर बनाए रखने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। अकिता प्रांत के युजावा शहर में एक व्यक्ति सड़क निर्माण स्थल पर भूस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता बताया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युजावा में बचाव कर्मियों ने नाव की मदद से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से 11 प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला है। यामागाटा प्रांत में सबसे त्यादा प्रभावित युजा और सकाटा कस्बों में एक घंटे में चार इंच से ज्यादा बारिश हुई। क्षेत्र के हजारों लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई। हालांकि, शरण लेने वाले लोगों की संख्या के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है।

पूर्वी जापान यामागाटा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से निलंबित कर दी गईं हैं। यहां भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

श्रीलंका में 21 सितंबर को होगा राष्ट्रपति चुनाव

कोलंबो (ईएमएस)।श्रीलंका के चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि देश में राष्ट्रपति चुनाव 21 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख 15 अगस्त घोषित की है।

चुनाव आयोग ने कहा कि देश के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल 17 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है। इतना ही नहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से करीब एक महीने और ज्यादा से ज्यादा दो महीने के बीच में ही किया जा सकता है। नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले गोटबाया राजपक्षे ने दक्षिण एशियाई देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच जुलाई 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद संसद में हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया।

हैरिस की नेतन्याहू को दो टूक.......गाजा में मासूमों की हत्या पर चुप नहीं रहूंगी

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कमला हैरिस से मुलाकात की। मुलाकात में कमला हैरिस ने हमास के द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों के मुक्त करवाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नेतन्याहू को दो टूक कहा कि गाजा में मासूमों की हत्या पर वे चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि तत्काल बातचीत के जरिए युद्धविराम की जरूरत है।

नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हैरिस ने कहा कि गाजा में युद्धविराम जरूरी है। यहां लाखों की संख्या में मासूमों की जान पर बनी है और वे भुखमरी के शिकार हैं। हैरिस ने कहा कि वह गाजा के लोगों की दिक्कतों को लेकर चुप नहीं रहेंगी। हैरिस ने कहा कि इजरायल को अपने बचाव का अधिकार है लेकिन बीते 9 महीने में जो कुछ भी हुआ वह बेहद खतरनाक और विनाशकारी है।

बता दें कि गाजा युद्ध से डेमोक्रेटिक पार्टी में भी इस मामले को लेकर दो धड़े बन गए हैं। हालांकि कमला का बयान पार्टी में बैलेंस बनाने वाला लगता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने कहा कि सभी लोग आतंकवाद, हिंसा, इस्लामोफोबिया और हेट की आलोचना करते हैं। हालांकि मानवता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गाजा में 20 लाख लोग भुखमरी के शिकार हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने जो बाइडेन से भी मुलाकात की थी।

नाटो देशों की तरह भारत को टेक्नोलॉजी और हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका

वॉशिंगटन(ईएमएस)। बीते रोज अमेरिकी सीनेट में लाए गए विधेयक में कहा गया है कि भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका को तत्पर रहने की जरुरत है। पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद और चीन से जुड़े सीमा विवाद जैसे मुददों पर भारत का सहयोग करना चाहिए। साथ ही प्रस्तावित विधेयक में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को भारत के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ करता है। जिस तरह अमेरिका नाटो के सहयोगियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उनकी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं ठीक वैसे ही हमें भारत के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद रुबियो ने कहा,कम्युनिस्ट चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति से इंडो पैसेफिक में अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन की इन हरकतों को सुधारने के लिए हमें भारत के साथ-साथ अपने सभी सहयोगियों की हरसंभव मदद करने की जरूरत है।

रुबियो द्वारा लाया गया यह बिल भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है लेकिन इस समय अमेरिका में चुनावी महौल है। समय की कमी और कांग्रेस के आपसी विभाजन के कारण इस विधेयक के आगे बढ़ने की संभावना न के बराबर है। लेकिन इस बात से यह साफ है कि अमेरिका की दोनों पार्टियां भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने को महत्व देती हैं। ऐसे में इस बिल को अगली कांग्रेस में फिर से पेश किया जा सकता है। विधेयक में कहा गया कि कम्युनिस्ट चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमें अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ अपने रणनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस विधेयक के अनुसार, अमेरिका भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए बढ़ते खतरों के जवाब में उसका समर्थन करेगा। और भारत के विरोधियों को रोकने के लिए भारत की हर संभव मदद भी करेगा इसके साथ ही वह अमेरिका रक्षा,नागरिक अंतरिक्ष के संबंध में भारत के साथ सहयोग करेगा।

पाकिस्तान को इस मामले में दो टूक कह देंगे कि यदि वह भारत के खिलाफ किसी भी तरह के आतंक में शामिल होता है तो उसको मिल रही तमाम सहायता और सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यह पहली बार है जब अमेरिकी कांग्रेस में इस तरीके का भारत-केंद्रित विधेयक पेश किया गया हो, जिसमें भारत को अपने नाटो सहयोगी के स्थान पर रखने और काट्सा प्रतिबंधों से छूट देने और भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध की बात कही गई हो।

इस कानून के पारित होने के बाद, यह भारत को रूसी सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए सीएएटीएसए प्रतिबंधों से एक सीमित छूट प्रदान करेगा जो वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जल्दी से जल्दी भारत की जरूरतों के हिसाब से सैन्य हथियार और सेवाओं को तैयार करने में और उनकों भारत तक पहुंचाने में अपनी भूमिका को निभाएगा। विधेयक के अनुसार यह अमेरिका के हित में हैं कि भारत के पास खतरों को रोकने की आवश्यक क्षमताएं हों। इस लिए भारत के साथ भी नाटो सहयोगियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसमें साथी देशों को हथियारों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी प्रदान की जाती है। भारत के साथ एक समझौता किया जाए और उसे दो वर्षों के लिए अतिरिक्त सैन्य सामग्री देना चाहिए।

साल 2022-23 में 10 में से 7 लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान में रहे

- इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर खरीदने-बेचने वालों की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई

नई दिल्ली (ईएमएस)। सेबी के एक अध्ययन में बताया गया ?कि साल 2022-23 में 10 में से 7 लोगों ने इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग से नुकसान उठाया। वहीं इसी दौरान इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर खरीदने-बेचने वाले लोगों की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2018-19 के मुकाबले ये संख्या तीन गुनी से ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ?जिन लोगों को शेयर बाजार में नुकसान हो रहा है वे ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा 30 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या भी शेयर बाज़ार में तेज़ी से बढ़ रही है। शेयर बाज़ार का नियमन करने वाली संस्था सेबी ने यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की। इसमें साल 2018-19, 2021-22 और 2022-23 के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। इसमें कोरोना काल भी शामिल है। इस रिपोर्ट के लिए देश के टॉप 10 ब्रोकरेज हाउस के ग्राहकों के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन 10 ब्रोकरेज हाउस के पास देश के कुल शेयर बाज़ार ग्राहकों का लगभग 86 फीसदी हिस्सा है।

इस रिपोर्ट को कई जानकारों ने देखा और सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है ?कि हर तीन में से एक व्यक्ति शेयर बाज़ार में इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। इसके अलावा, इस तरह के ट्रेड में 30 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। साल 2018-19 में ये संख्या 18 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 48 फीसदी हो गई है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कारोबार करता है तो उसके नुकसान होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में से 80 फीसदी लोग घाटे में रहे हैं। साल 2022-23 में नुकसान उठाने वाले लोगों ने अपने नुकसान का 57 फीसदी हिस्सा कारोबार के खर्चों में लगाया, जबकि मुनाफा कमाने वालों ने अपने मुनाफे का सिर्फ 19 फीसदी हिस्सा खर्च किया। इसके अलावा कम उम्र के लोगों में नुकसान उठाने वालों की संख्या ज़्यादा है। साल 2022-23 में 76 फीसदी युवा ट्रेडर घाटे में रहे। सेबी का मानना है कि इस रिपोर्ट से लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में होने वाले जोखिम के बारे में पता चलेगा। शेयर बाज़ार में फ्यूचर और ऑप्शन वाले हिस्से में ज़्यादातर लोगों को नुकसान हुआ है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में 89 फीसदी लोगों ने इस हिस्से में पैसा गंवाया। हर व्यक्ति ने औसतन 1.1 लाख रुपये का नुकसान उठाया। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान एफएंडओ में कारोबार करने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। साल 2019 में ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख थी, जो साल 2021 में बढ़कर 45 लाख हो गई। यह संख्या 500 फीसदी से ज़्यादा बढ़ी है।

इमरान को जेल से छुड़ाएगा अमेरिका

सीक्रेट दौरे पर पाक आएगा अमेरिकी दल; इमरान की रिहाई के पक्ष में फौज के 5 कमांडर

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को 9 में से 5 कोर कमांडरों ने सुझाव दिया है कि पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से बाहर आने दिया जाए। ऐसा करके दुनियाभर के निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिलेगा और देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी।

अभी जनरल असीम मुनीर अड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि जेल से बाहर आने के बाद इमरान को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इमरान उन पर निशाना साधेंगे। मौजूदा हालातों को देखते हुए माना जा रहा है कि इमरान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ न्यायपालिका, पाक सेना या शहबाज शरीफ के बूते नहीं होगा। यह पाकिस्तान से हजारों मील दूर से होगा, क्योंकि इमरान की रिहाई के समझौते में अमेरिका का हाथ होगा। अगले हफ्ते एक अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान आ रहा है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सरकार और सेना के साथ इस संबंध में कोई गुप्त समझौता भी कर सकता है।

कैदी नंबर 804, कभी ना माने हार

इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान में सॉन्ग एलबम भी जारी हो रहे हैं। इनमें मशहूर सिंग सारा अल्ताफ का एलबम कैदी नंबर 804 सबसे पॉपुलर है। इसके बोल हैं- कैदी नंबर 804, कभी ना माने हार। इमरान की पार्टी पीटीआई ने इसे अपना ऑफिशियल सॉन्ग बनाया है। एक अन्य एलबम नाक दा कोका में भी पीएम इमरान की कैद का जिक्र किया गया है। इन दोनों एलबमों को अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। उधर, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने ऐलान किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई के लिए संसद के बाहर भूख हड़ताल की जाएगी।

भारतवंशी कमला हैरिस को मिला ओबामा का साथ

-पत्नी मिशेल ने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए समर्थन दिया, उम्मीदवारी लगभग तय

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने भारतवंशी कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन कर दिया है। दोनों ने शुक्रवार को फोन पर कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में ओबामा दंपती का समर्थन मिलने पर कमला हैरिस खुशी जता रही हैं। बाइडेन ने 22 जुलाई को रेस छोड़ने का ऐलान किया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए समर्थन किया था। इसके बाद से अब तक कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने कमला हैरिस का पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर समर्थन किया है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब तक दूरी बनाई हुई थी लेकिन अब जाकर उन्होंने भी कमला हैरिस के लिए हामी भर दी है। कमला हैरिस को पहले ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी अगले महीने 1 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मेलन बुला रही है, जिसमें कमला हैरिस को औपचारिक उम्मीदवार बनाने के लिए वोटिंग होगी।

जीत दिलाने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे

बराक ओबामा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें बराक और मिशेल दोनों उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को फोन कर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। बराक ओबामा ने कमला हैरिस से कहा- मिशेल और मैं आपका समर्थन करने के लिए और आपको इस चुनाव में जीत दिलाने के और व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। इसके जवाब में कमला हैरिस ने ओबामा दंपती को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया और उनकी दशकों पुरानी दोस्ती के लिए एहसान भी जताया। कमला हैरिस ने फोन पर कहा- आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

अमेरिकी संसद में एक बिल पेश कर की गई मांग , भारत को नाटो जैसी तवज्जो मिले

-पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद हो, चीन को काउंटर करने में मिलेगी मदद

वाशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिकी संसद में भारत को जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नाटो सहयोगियों के स्तर पर ही तवज्जो देने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो ने इसके लिए संसद में एक बिल पेश किया है। बिल में कहा गया है कि भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर ही तकनीकी सहायता की जाए। इसके अलावा आतंकवाद के खतरे से निपटने में भी साथ दिया जाए। इस बिल को अमेरिका-भारत डिफेंस को-ऑपरेशन एक्ट नाम दिया गया है।

प्रस्ताव पेश करने के बाद अमेरिकी सांसद ने कहा कि कम्युनिस्ट चीन इंडो-पैसेफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता रहता है। ऐसे में यह जरूरी है कि अमेरिका भारत जैसे अपने सहयोगियों को चीन से निपटने में मदद करे।

रूस से हथियार खरीदने पर नहीं लगेगी पाबंदियां

अगर यह बिल पास होता है तो अमेरिका भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए रक्षा, तकनीक और आर्थिक स्तर पर मदद करेगा। इसके अलावा दोनों देशों में मेडिसिन, मिलिट्री और सिविल स्पेस के क्षेत्र में भी को-ऑपरेशन बढ़ेगा। इसके अलावा रूस से इक्विपमेंट खरीदने पर भारत पर पाबंदियां भी नहीं लगेंगी। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, यह पहली बार है जब अमेरिकी संसद में भारत को फोकस में रखकर इस तरह का बिल पेश किया गया है।

भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की उठी थी मांग

इससे पहले पिछले साल अमेरिकी संसद में भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की भी मांग उठी थी। अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रासंफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर 'नाटो प्लस' का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई थी। कमेटी का मानना था कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ-साथ क्वॉड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। हालांकि, भारत ने स्पष्ट संकेत दिया था कि वह 'नाटो प्लस' में शामिल नहीं होना चाहता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ किया था कि 'नाटो प्लस' के दर्जे के प्रति भारत ज्यादा उत्सुक नहीं है।

शेयरों में लगाएं पैसा या सोने में करें निवेश, जानिए निवेश सलाहकारों से

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने की कस्टम डयूटी घटा कर 6 फीसदी कर दी है, इससे देश में सोने के भाव में ?गिरावट आ गई है। वैसे निवेश के लिहाज से अगर हम पिछले पांच वर्षों को देखें तो सोने ने शेयरों से ज्यादा रिटर्न दिया है। इस अवधि में निफ्टी 50 का रिटर्न 13.95 फीसदी तो सोने का 16.21 फीसदी रहा है। हालांकि, 20 वर्ष और 10 वर्ष में शेयर बाजार का रिटर्न सोने से ज्यादा रहा है। ऐसे मे अब सवाल यह है कि एक आम निवेशक को सोने में निवेश ज्यादा करना चाहिए या फिर शेयर बाजार में? निवेश सलाहकारों का कहना है कि साल 2024 की दूसरी छमाही में स्टॉक्स और गोल्ड दोनों में स्थिर वृद्धि की उम्मीद है। मिड टर्म में निफ्टी 50 25,600-26,000 तक पहुंच सकता है, जबकि साल के आ?खिर तक सोने का भाव 81,500 तक जा सकता है।

ऐसे में निवेशकों को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर दोनों में धन आवंटित करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेहता इक्विटीज लिमिटेड के एक वीपी कमोडिटीज का सुझाव है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और शेयरों से कुछ लाभ निकालकर सोने में निवेश करना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशक आमतौर पर अपने एसेट का 10-15 फीसदी कीमती धातुओं में निवेश करते हैं, लेकिन वर्तमान में इस आवंटन को बढ़ाकर 30-35 फीसदी कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि यूएस दर में कटौती के बाद सोने में और भी वृद्धि हो सकती है। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एक ??निवेश सलाहकार कहते है कि निफ्टी मिड टर्म में 25,600-26,000 के स्तर को छू सकता है। सोना भी इस साल के अंत तक 81,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर धन आवंटित करें। वर्तमान में स्टॉक्स और गोल्ड दोनों ही रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं। ये दोनों ही विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक आने की संभावना

गुजरात सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून लाएगी

गांधीनगर, २६ जुलाई । पूरे देश में भ्रष्टाचार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है । सरकार लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है । इसी के तहत गुजरात सरकार भी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कानून बना रही है । इस संबंध में विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है । बता दें कि १२ साल पहले केंद्र सरकार ने रिटायर भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया था ।

राजकोट के बेहद भ्रष्ट पूर्व टीपीओ मनसुख सगाथिया के मामले से हैरान सरकार अगले सत्र में बिल लाने की तैयारी में जुट गई है । मनसुख सगाथिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया गया है । प्रस्तावित कानून सरकार को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होते ही सभी संपत्तियों और संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देगा ।

गुजरात में सरकारी कार्यालयों और जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । भ्रष्ट अधिकारी अपनी अतिरिक्त कमाई को कीमती जमीनों, फार्म हाउसों और अन्य संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं । ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद संपत्ति जब्त करने के लिए अदालती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है । हालांकि, अब सरकार केस दर्ज कर आय से अधिक संपत्ति जब्त कर सकेगी । इसके अलावा जमानत के लिए भी कड़े नियम बनाए जा सकते हैं । देश में इससे पहले २००६ में उड़ीसा सरकार और २००९ में बिहार सरकार ने इस संबंध में कानून पारित किया था । लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देने पर रोक लगा दी गई है । प्रस्तावित कानून में न केवल भ्रष्ट अधिकारी बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और मिश्रित नामों से खरीदी गई संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है । गुजरात में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां ड्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार तो किया गया लेकिन रिटायरमेंट के बाद उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई । केंद्र सरकार द्वारा १२ साल पहले बनाए गए कानून के तहत रिटायरमेंट के बाद भी किसी अधिकारी की संपत्ति जब्त की जा सकती है ।

गुजरात सतर्कता आयोग की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में सचिवालय के २१ विभागों में भ्रष्टाचार की कुल १२,०४९ शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे ज्यादा २९९६ शिकायतें शहरी विकास विभाग और १७३५ शिकायतें राजस्व विभाग से थीं । आयोग ने साल २०२० में ८३७३ शिकायतें दर्ज कीं और ९८३ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की । २०२१ में ११,२२६ शिकायतों में से ११४८ मामलों में और २०२२ में १२६०८ शिकायतों में से १५४८ मामलों में कार्रवाई की अनुशंसा की गई ।

गुजरात सरकार ने जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की आवश्यक दवा सूची में वृद्धि की है

गांधीनगर, २६ जुलाई । स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने जीवन रक्षक स्वास्थ्य दवाओं की आवश्यक दवा सूची २०२४-२५ में ६६५ नई दवाएं शामिल की हैं। पहले राज्य सरकार की आवश्यक औषधि सूची में ७१७ औषधियाँ थीं, जो अब वर्ष २०२४-२५ में बढ़कर १३८२ हो गयी हैं । प्रदेश के हर मरीज को सर्वोत्तम इलाज और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है । ये दवाएं राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों से लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सिविल अस्पतालों तक मुफ्त उपलब्ध होंगी ।

दवाओं की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल आवश्यक दवा सूची को संशोधित किया जाता है। इस वर्ष जोड़ी गई नई दवाओं में कैंसर रोधी, कैंसर रोधी, संक्रमण रोधी, हृदय संबंधी, मधुमेह, बीपी शामिल हैं । साथ ही, किडनी रोग से जुड़ी जीवन रक्षक दवाएं भी इसमें शामिल की गई हैं । राज्य सरकार की आवश्यक औषधि सूची में प्राथमिक चिकित्सा के लिए ३०८ औषधियाँ, द्वितीयक चिकित्सा के लिए ४९५ औषधियाँ और तृतीयक चिकित्सा के लिए १३४९ औषधियों के अलावा विशेष चिकित्सा के लिए ३३ औषधियाँ शामिल हैं ।

इस दवा सूची में ५४३ टैबलेट, ३३१ इंजेक्शन, ३०० सर्जिकल और २०८ अन्य दवाएं शामिल हैं । वर्ष २०२२-२३ की दवा सूची में २४ हृदय संबंधी दवाएं थीं, जो वर्ष २०२४-२५ में बढ़कर ११७ हो गई हैं । इसी तरह, संक्रमणरोधी दवाएं १२० से बढ़कर १९९ हो गई हैं, कैंसररोधी दवाएं १३ से बढ़कर ४७ हो गई हैं, न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग संबंधी दवाएं ५२ से बढ़कर १२३ हो गई हैं, इस तरह कुल १२ बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाएं बढ़ाई गई हैं।

हाईकोर्ट ने सरकार से स्कूलों में अग्नि सुरक्षा की जांच करने और उन्हें बंद करने को कहा

अहमदाबाद, २६ जुलाई । राजकोट में आग लगने की घटना के बाद हाई कोर्ट ने फायर सेफ्टी के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फायर सेफ्टी की कमी के कारण सिस्टम ने प्री-स्कूल बंद कर दिए हैं और कोई नोटिस या समय नहीं दिया गया है. यहां तक कि सरकार ने भी अग्नि सुरक्षा लागू करने के लिए कोई अधिसूचना या निर्देश जारी नहीं किये हैं. आपको स्कूलों में अग्नि सुरक्षा सुविधाओं की जांच करने का निर्देश दिया जाता है । सिस्टम को बहुत अधिक बिजली की खपत नहीं करनी चाहिए. जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है, आपने तुरंत सख्त कार्रवाई की है । हमने आपसे स्कूलों में अग्नि सुरक्षा लागू करने के लिए कहा था, न कि स्कूलों को बंद करने के लिए ।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया है. हमने किसी स्कूल को बंद करने के लिए नहीं कहा है । अग्नि सुरक्षा के कारण कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा । जहां तक स्कूल की बात है तो छत पर बड़ी टंकी नहीं रखी जा सकती, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से नीचे सिंटेक्स टंकी लगाने को कहा गया । ऐसा लगता है कि कोई गलतफहमी है. हम केवल स्कूलों में अग्नि सुरक्षा को तेज़ बनाने का प्रयास करते हैं । कोर्ट ने कहा कि अधिकारी बैठकर एक गाइडलाइन बनाएं और उसे लागू करें. स्कूलों में फायर सेफ्टी के मुद्दे पर जांच कर एक अवधि के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसके तत्वावधान में स्कूल को सील करने की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए । सरकार को अग्नि सुरक्षा पर उचित निर्देश दें । प्री-स्कूल दिन के दौरान चलता है । छोटे बच्चों के माता-पिता कार्यरत हैं । ये विद्यालय आवासीय भवनों में संचालित होते हैं । आप यहां अग्नि सुरक्षा उपाय तो करते हैं लेकिन बहुत अधिक कार्रवाई नहीं करते ।

गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी-नाले छलके, कई नदियां उफान पर

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के नदी-नाले छलक गए हैं कई नदियां उफान पर हैं तो कई खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं गुजरात में मूसलाधार बारिश के कारण राज्य की नदियों में काफी पानी आ गया हैं गुजरात के साथ-साथ ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं दक्षिण गुजरात के तापी की मिंडोला, व्यारा, वाल्मिकी नदियों में बाढ़ से हालात हैं तो वडोदरा की ढाढर और छोटाउदेपुर की ओरसंग नदी उफान मार रही हैं छोटाउदेपुर और उसके ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण ओरसंग नदी समेत उसके तटबंध ऑवर फ्लो हो गए हैं वहीं वडोदरा में हाहाकार मचाने वाली विश्वामित्री का जलस्तर घटने से लोगों को बड़ी राहत मिली हैं बारिश थमने से नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है और निचले इलाकों में पानी उतरने लगा हैं दक्षिण गुजरात के तापी जिले के वालोड में वाल्मिकी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया हैं तापी जिले की नदियों में बाढ़ आने से पानी कई गांवों में घुस गया हैं वालोड और व्यारा के कई गांवों में नदी के पानी से घिरे लोगों की हालत गंभीर हो गई हैं घर में फंसे लोगों के लिए बचाव कार्य किया जा रहा हैं दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले में पूर्णा नदी से हाहाकार मच गया हैं पूर्णा नदी खतरनाक स्तर को पार कर गई है और नवसारी में पानी 5 से 10 फीट तक पहुंच गया हैं ऐसे में लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया हैं इस स्थिति के बीच शांतादेवी इलाके के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया हैं फायर विभाग की टीमें पानी के बीच लोगों को बचा रही हैं पानी इस कदर भर गया है कि लोगों को घरों के छतों पर रुकना पड़ रहा हैं जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा हैं सड़कें नदी-नालों में तब्दील हो चुकी हैं नवसारी की कई हाउसिंग कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को जीना दूभर हो गया हैं लोगों का घरेलू सामान समेत वाहन पानी में डूब गए हैं कई घरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई हैं नवसारी में 31 वर्षीय भूमिका शाह नामक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई बताया जाता है कि वसुधारा एपार्टमेंट में समय पर रेस्क्यू नहीं किए जाने से भूमिका शाह की मौत हो गई

गुजरात में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट, 24 घंटों में 111 तहसीलों में बारिश

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में मानसूनी बरसात से कई जिलों के हालात बिगड़ गए हैं आगामी 3 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना के चलते राज्य कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हैं मौसम विभाग के मुताबिक आज नवसारी, सूरत, वलसाड, दमण और दादरा नगर हवेली में ऑरेंज अलर्ट दिया गया हैं जबकि 20 से ज्यादा जिलों में यलो अलर्ट दिया गया हैं इन जिलों में गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, आणंद, भरुच, नर्मदा, तापी, डांग, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल और छोटाउदेपुर इत्यादि शामिल हैं वहीं 27 जुलाई को सूरत, नवसारी, वलसाड, दमण और दादरा नगर हवेली में ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया हैं 28 जुलाई को राज्य के गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, भरुच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दादरा नगर हवेली, साबरकांठा, अरवल्ली और महीसागर जिलों में अलर्ट जारी किया गया हैं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 111 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात के तापी जिले के डोलवान तहसील में 7 इंच, डांग जिले के सुबीर तहसील में 6 इंच और नवसारी जिले के नवसारी तहसील में 6 इंच बारिश हुई जबकि तापी जिले के उच्छल तहसील में 5 इंच, महुवा तहसील में 5 इंच बारिश हुई। सूरत जिले में 5 इंच और नवसारी जिले के जलालपोर तहसील में 5 इंच बारिश हुई हैं जबकि नवसारी जिले के गणदेवी तहसील में 4 इंच और तापी जिले के वालोड तहसील में 4 इंच बारिश दर्ज की गई हैं राज्य के स्टेट इमर्जंसी ऑपरेशन सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे राज्य में मौसम की औसत बारिश 54 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई जिसमें सबसे ज्यादा 75 फीसदी बारिश कच्छ जोन में दर्ज की गई हैं इसके अलावा सौराष्ट्र जोन में मौसम की कुल औसत बारिश 73 फीसदी, दक्षिण गुजरात में 66 फीसदी, उत्तरी गुजरात में 29 फीसदी और पूर्व-मध्य गुजरात में 33 फीसदी बारिश हुई हैं

अहमदाबाद मण्डल पर रेल टिकट किराया भुगतान हेतु कोड की सुविधा उपलब्ध

अहमदाबाद (ईएमएस) प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप तथा रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अहमदाबाद मंडल के सभी काउंटरों पर क्यूआर कोड डिवाइस लगाने का कार्य प्रगति पर है। रेल यात्रियों को टिकट किराये का भुगतान करने के लिए कोड डिजिटल माध्यम की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस नई पहल के तहत कोड-डिजिटल माध्यम को अहमदाबाद मण्डल के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों जिसमें अहमदाबाद, मणीनगर, असारवा तथा वटवा स्टेशनों के सभी अनारक्षित टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड के माध्यम से अनारक्षित टिकट का भुगतान स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा मण्डल के अन्य सभी स्टेशनों पर भी अनारक्षित तथा आरक्षित काउंटरों पर शीघ्र ही क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। रेल यात्रियों को अब टिकट किराया भुगतान करने के लिए ळऊए मोबाइल एप, ऊन्र (कोड की सुविधा सहित), इध्ए और ळइ्ळ जैसे डिजिटल भुगतान के विभिन्न विकल्प पहले से उपलब्ध हैं। इस प्रकार की डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक उपयोगी और सुगम बनाने के उद्देश्य से अहमदाबाद मण्डल ने इसका विस्तार किया है।

मुख्यमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' के अंतर्गत राज्यव्यापी अर्बन फॉरेस्ट अभियान का गांधीनगर से शुभारंभ किया

गांधीनगर (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित देशव्यापी महाअभियान 'एक पेड़ मां के नाम' को शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने के उम्दा आशय से पूरे राज्य में 31 अगस्त तक अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने का अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर महानगर पालिका क्षेत्र में स्थित कोबा इलाके में बरगद का पौधा लगाकर राज्य व्यापी अर्बन फॉरेस्ट अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस केअवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाने का आह्वान किया था। पर्यावरण को बचाने के प्रधानमंत्री के इस उम्दा दृष्टिकोण को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों तकले जाने के लिए पूरे राज्य में आगांमी 31 अगस्त,2024तक अर्बन फॉरेस्ट अभियान का आयोजन किया गया है। अर्बन फॉरेस्ट अभियान के अंतर्गत राज्य के शहरों में वन एवं वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ राज्य की महानगर पालिकाओं, 157 नगर पालिकाओं और सभी 165 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत अर्बन फॉरेस्ट अभियान आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के व्यक्तिगत दायित्व के विषय में लोगों के बीच और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए नागरिकों, गणमान्य लोगों और विभिन्न संस्थानों की सहभागिता से शहरी वनीकरण, मियावाकी वन और ग्रीन स्पेस से संबंधित अन्य कार्यक्रम सभी शहरों में आयोजित किए जाएंगे। 'एक पेड़ मां के नाम' विशेष महाअभियान के अंतर्गत महानगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्र में हर वॉर्ड और जोन में विशेष स्थान पर वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपे गए पौधों की देखभाल के लिए इस स्थान के चारों ओर सुरक्षा के लिए बाड़ या दीवार का निर्माण भी किया जाएगा। कोबा में अर्बन फॉरेस्ट अभियान के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों ने एक-एक पौधा लगाया। कोबा में 4700 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्रफल वाले भूखंड में अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण होगा। यहां नीम, आम, इमली, बोरसली और आंवला जैसे कुल 1500 पौधे रोपे जाएंगे। इस अवसर पर गांधीनगर महानगर पालिका की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर (द) के विधायक अल्पेश ठाकोर, गांधीनगर (उ) की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, उप महापौर नटवरजी ठाकोर, जिला कलेक्टर मेहुल दवे, मनपा आयुक्त जे.एन. वाघेला सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

गुजरात हाई कोर्ट ने आज पुलिस भर्ती मामले में गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया

अहमदाबाद, २६ जुलाई । गुजरात हाई कोर्ट ने आज पुलिस भर्ती मामले में गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया । हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि पुलिस भर्ती के मुद्दे पर सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? उन्होंने यह भी सवाल किया कि २५२ पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति और अन्य भर्तियां क्यों लंबित हैं और सरकार पुलिस कर्मियों की भर्ती में तेजी क्यों नहीं लाती बल्कि उन्हें तुरंत पदोन्नत कर देती है । गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने लंबे समय से पुलिस कर्मियों की भर्ती नहीं की है । इस कारण स्टाफ की भारी कमी है ।

कोर्ट ने सरकार को यह बताने का आदेश दिया कि प्रमोशन और भर्ती नियम किसने बनाये । कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया का मामला कोर्ट में लंबित है । जबकि कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं. दूसरी ओर, अदालत ने कहा कि पदोन्नति आदेशों में तेजी लाने की दोहरी नीति है।

याचिकाकर्ता के वकील हार्दिक ब्रह्मभट्ट ने कहा कि सरकार ने अदालत से कहा था कि हम पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत करना चाहते हैं लेकिन हमने जीपीएससी से मंजूरी मांगी है और प्रक्रिया चल रही है । हार्दिक ब्रह्मभट्ट ने जानकारी दी कि जब कोर्ट ने कहा कि आपका अपना भर्ती बोर्ड है तो आप जीपीएससी पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, कोर्ट ने यह भी हवाला दिया कि प्रमोशन और भर्ती के लिए एक ही बोर्ड होना चाहिए ।

धोराजी-उपलेटा तालुक में आंधी-तूफान के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया

धोराजी,२६ जुलाई । धोराजी-उपलेटा तालुका में भारी बारिश और बादल छाए रहने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । अब सभी लोग मेघराजा से खमैय्या करने की विनती कर रहे हैं । कलेक्टर ने विकट स्थिति में उपलेटा तालुका का दौरा किया है लेकिन एक भी अधिकारी धोराजी तालुका में नहीं गया है और धोराजी में आयोजित बैठक में ग्राम नेताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान न करने और न बुलाने की असंवेदनशील और असंवेदन शील प्रणाली के खिलाफ बहुत आक्रोश है बैठक में मीडियाकर्मी । धोराजी तालुक के छड़वा वादर में ५ दिनों में ५८ इंच और चिचोड़ गांव में ८० इंच बारिश के बावजूद न तो मामलतदार, न विधायक और न ही डे कलेक्टर! आज तक, धोराजी-उपलेटा तालुका के कई गांव अलग-थलग पड़े हुए हैं । सीवन के किनारे की सड़कें बह गई हैं ।

इस संबंध में सरकार को तुरंत इस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल सर्वेक्षण करना चाहिए, भले ही सरकार किसानों को २०,००० रुपये की मदद करे, लेकिन इसे इकट्ठा करना संभव नहीं है ।

अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का आइपीओ 30 जुलाई, 2024 को खुलेगा

अहमदाबाद, 26 जुलाई, 2024: अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ठेंख्लशएठ या ठकंपनीठ), का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को खुलेगा। यह एक अगस्त को बंद होगा।

इस ऑफ में कंपनी द्वारा इतनी संख्या में इकिट्टी शेयर (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये) का नया निर्गम शामिल है, जिसका कुल मूल्य 680 करोड़ रुपये है (ठफ्रेश इश्यूठ) और कंपनी के कुछ मौजूदा शेयरधारकों (ठबिक्री करने वाले शेयरधारकठ) द्वारा 17,7,330,435 एकिटी शेयर (ठपेश किए गए शेयरठ) का ऑफर फॉर सेल शामिल है। ऑफर फॉर सेल में संजीव जेन द्वारा 1,512,000 इकिटी शेयर तक, संदीप जैन द्वारा 1,512,000 तक इक्विटी शेयर (सामूहिक रूप से, ठप्रवर्तक विक्रेता शेयरधारक) और रूबी क्यूसी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (ठरूबी क्यूसीठ या ठइन्वेस्टर सेलिंग शेयरधारकठ) (विक्रय शेयरधारकों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ऐसा प्रस्ताव, ठबिक्री के लिए प्रस्ताव) द्वारा 14,306,435 तक इक्विटी शेयर शामिल हैं। रूबी क्यूसी को काड्रिया कैपिटल द्वारा समर्थित है, जो एशिया में एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्रित निजी इक्विटी फंड है।

ऑफर का मूल्य बैंड 646 से 679 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (मूल्य बैंठ) तय किया गया है। न्यूनतम 22 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 22 इकिटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती है (न्यूनतम बोली लॉट)

कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से मिली रकम का उपयोग (1) कंपनी के ऋण की चुकौती/पूर्व भुगतान; (ग) अपनी सहायक कंपनियों अर्थात् मैक्सक्योर न्यूट्रैवेटिक्स लिमिटेड और प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के ऋण की चुकौती/पूर्व भुगतान; (गग) कंपनी की वृद्धिशील कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए फाइनेंस जुटाने; (ग=) अधिग्रहण के माध्यम से इनआर्गनिक विकास पहलों को आगे बढ़ाने बढ़ाने; और (=) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एंबिट प्राइवेट लिमिटेड ऑफ़र के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं ("BRLMS") I इसमें उपयोग किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, का वही अर्थ होगा जो RHP में उन्हें दिया गया है।

ठाकोर समाज के लिए उपयोग किए जाते एक शब्द पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात सरकार ने राज्य में ठाकोर समाज के लिए उपयोग किए जाते एक शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया हैं सांसद भरतसिंह डाभी की इस संदर्भ में की गई पेशकश के बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने यह फैसला किया हैं गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया हैं जिसमें ठाकोर समुदाय के लिए इस्तेमाल किए गए एक शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के इस पत्र में जहां भी इस प्रतिबंधित शब्द का जिक्र है, वहां यह स्पष्ट किया गया है कि ठाकोर समझा जाना चाहिए यदि इस निषिद्ध शब्द का उल्लेख स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या राजस्व रिकॉर्ड, पंचायत रिकॉर्ड और अन्य सरकारी रिकॉर्ड में किया गया है,

किज़ी अपैरल्स लिमिटेड बीएसई/एसएमई आई पी ओ के ज़रिए 558.18 लाख रुपये जुटाएगी

जयपुर, राजस्थानः- रेडीमेड गारमेंट्स के अग्रणी निर्माता और व्यापारी किज़ी अपैरल्स लिमिटेड ने 558.18 लाख रुपए जुटाने के लिए अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। आईपीओ बीएसई/एसएमई के माध्यम से संचालित किया जाएगा और 30 जुलाई, 2024 को खुलेगा।

हमारी कंपनी की शुरुआत नवंबर 2017 में मेसर्स आइका क्रिएशन्स नाम से एक प्रोप्राइटरशिप के रूप में हुई थी। मेसर्स आइका क्रिएशन्स की स्थापना हमारे ग्राहकों की एंड-टू-एंड आवश्यकताओं को पूरा करके और समग्र गुणवत्ता मानकों को बढ़ाकर विनिर्माण उद्योग में क्रांति लाने की दृष्टि से की गई थी। 24 मार्च, 2023 को इसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठकिज़ी अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेडठ में बदल दिया गया। इसके बाद, 21 जुलाई, 2023 को आयोजित ईजीएम में हमारे शेयरधारकों द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के अनुसार, हमारी कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर ठकिज़ी अपैरल्स लिमिटेड कर दिया गया।

कंपनी 26,58,000 इक्विटी शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जारी करने की योजना बना रही है, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर होगा तथा निर्गम मूल्य 21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर होगा (जिसमें 11 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है)। निर्गम का कुल आकार 558.18 लाख रुपये है। इस निर्गम का मुख्य प्रबंधक इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है।

किज़ी अपैरल्स लिमिटेड अपनी जॉब वर्किंग सेवाओं के लिए जानी जाती है, जो प्रमुख भारतीय ब्रांडों और वेडिंग कलेक्शन लीडर्स को आपूर्ति करती है। कंपनी अपने उत्पादों को अपनी वेबसाइट और राजस्थान के स्थानीय बाजारों के माध्यम से बेचती है, और सुविधाजनक ऑनलाइन भुगतान सुविधाएँ प्रदान करती है। किरण नैथानी, उम्र 35, एक प्रतिभाशाली डिजाइनर हैं, जिनके पास व्यापक अनुभव और अपनी यात्राओं से प्राप्त वैश्विक अंतर्दृष्टि है। वह प्रतिदिन डिजाइनरों के साथ सहयोग करती हैं, अपनी रचनात्मकता और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को ब्रांड में शामिल करती हैं।

थम्सअप के ओलम्पिक कैम्पेन में नजर आई 'थम्सअप' की असली ताकत

नई दिल्ली, 24 जुलाईः थम्सअप, कोका-कोला कंपनी का एक अरब डॉलर का भारतीय ब्रैंड, ने अपने नए कैम्पेन 'उठा थम्सअप, जगा तूफान' की घोषणा की है, जो पेरिस 2024 ओलम्पिक और पैरालिम्पिक खेलों के लिए है। यह कैम्पेन एक सरल, लेकिन दमदार विचार पर आधारित हैः 'थम्सअप' के असर से खिलाड़ी अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे खिलाड़ी अपने आप में गजब के 'तूफान' हैं और वे देश को सिखाते हैं कि हमें अपनी भीतरी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कोई भी एक ही रात में चैंपियन नहीं बनता। जब भी कोई खिलाड़ी मुश्किल हालात या संकोच का सामना करता है, तो उसके समर्थक, कोच, दोस्त और परिवार वाले अंगूठा उठाकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। वह लगातार जीतने के लिए खेलता है और यही इस कैम्पेन का संदेश है।

इस कैम्पेन पर बात करते हुए, कोका-कोला इंडिया और साउथ-वेस्ट एशिया में स्पार्कलिंग फ्लेवर्स की सीनियर कैटेगरी डायरेक्टर सुमेली चटर्जी ने कहा, ठहम ओलम्पिक और पैरालिम्पिक में भारत के सपने का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं। पिछले 4 सालों में हमारे खिलाड़ियों ने दुनियाभर के खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिस पर हमें गर्व है। पेरिस 2024 एक ऐतिहासिक मौका होगा और हमें गर्व है कि हम अपने खिलाड़ियों के सफर में उनका साथ दे रहे हैं। हमारा मानना है कि अंगूठा उठाने जैसा छोटा सा प्रोत्साहन किसी भी पल में बड़ा फर्क ला सकता है - न केवल खिलाड़ियों के लिए, बल्कि सभी के लिए। और जब इसके साथ थम्सअप जैसा मशहूर ब्रैंड हो, तो यह दृढ़ता और अटूट लगन का प्रतीक बन जाता है।

स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ में तिमाही-दर-तिमाही पर दोगुनी वृद्धि के साथ मजबूत विकास दर्ज किया

मुंबई, 26 जुलाई, 2024 – बीएसई पर लिस्टेड (एँ एम्जि म्दा ध्शः 539017) और छोटे शहरो और ग्रामीण इलाको पर ध्यान केन्द्रित करनेवाली होम फाइनेंस कंपनी स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (स्टार एचएफएल) ने रिटेल होम फाइनेंस क्षेत्र में अपनी प्रगति को आगे बढाना जारी रखा है और 30 जून, 2024 को समाप्त होती तिमाही के लिए मजबूत व्यापारिक और वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है।

इस तिमाही के दौरान स्टार एचएफएल ने 30 जून, 2024 को समाप्त होती तिमाही के लिए सभी व्यवसायों में माइलस्टोन्स दर्ज किए है जो इस प्रकार हैः

देयता स्केल में वृद्धिःलॉन बुक वृद्धि में सहायता के लिए स्टार एचएफएल के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मजबूत संबंध हैं। 6 बैंकों और 11 वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वर्तमान उधारी रु. 335.35 करोड़ है। देनदारी पाइपलाइन मजबूत है और वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय योजना के अनुसार योजना बनाई गई है।

इस तिमाही के प्रदर्शन पर बोलते हुए, स्टार एचएफएल के सीईओ श्री कल्पेश दवे ने कहा, ''स्टार एचएफएल एसेट गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। अब हम रु. 500 करोड़ एयूएम के लक्ष्य को पार करने की दहलीज पर हैं और अगली कुछ तिमाहियों में रु. 1000 करोड़ एयूएम की अगली छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। ब्रान्च नेटवर्क अब 280 से अधिक कर्मचारियों की स्टाफ क्षमता के साथ 34 स्थानों पर मल्टी-स्पेस के साथ विविध है और मौजूदा और नए भौगोलिक क्षेत्रों में 50 से अधिक स्थानों तक विस्तार करने का लक्ष्य है।

रिटेल हाउसिंग फाइनेंस की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए, श्री कल्पेश दवे ने कहा, ''ईर्ष्भ-र्ळेह 2.0 के माध्यम से ईर्ष्भ का पुनः लॉन्च जिसमें 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण में वित्तीय सहायता पर ध्यान देने के साथ रु. 10 लाख करोड़ का आवंटन शामिल है, यह पहली बार घर खरीदने वालों के लिए और इस क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए अच्छा संकेत है।

अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली तीन जोड़ी स्पेचशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर अहमदाबाद मण्डल से चलने/होकर गुजरने वाली तीन जोड़ी स्पेकशल ट्रेनों के फेरे विस्तासरित किए गए हैं। इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1.ट्रेन संख्या 09493 अहमदा बाद-पटना साप्ताहिक स्पेशल, जिसे पहले 28 जुलाई, 2024 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 25 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब उसे 27 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09425 साबरमती-हरिद्वार द्वि-साप्ताहिक स्पेशल, अब 29 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार-साबरमती द्वि-साप्ताहिक स्पेशल, अब 30 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 3. ट्रेन संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल जिसे पहले 25 जुलाई, 2024 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 29 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

ट्रेन संख्यात 09207 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल जिसे पहले 26 जुलाई, 2024 तक अधिसूचित किया गया

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई–प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना क्रमांक एस/38/2024 दिनांक 24.07.2024

क्र. सं.	वस्तु का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
511	ईओटी क्रेन-65टी क्षमता	2 नग	22-Aug-24
512	एस्कॉर्ट्स के एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम के लिए किट अवश्य बदलें।	15 सेट	22-Aug-24
513	CASNUB बोगी के लिए बोगी सेंटर पिवट टॉप	3570 नग	22-Aug-24
514	वॉशर के साथ नक्कल पिवट पिन	14962 नग	22-Aug-24
515	VRLA, वाल्व विनियमित (सीलबंद) लीडएसिड बैटरी क्षमता 2V 200AH	960 नग	26-Aug-24
516	कॉइल स्प्रिंग के लिए वायुहीन केन्द्रापसारक शॉट ब्लास्टिंगप्लांट	1 नग	26-Aug-24
517	एक्सल बॉक्स के लिए पिछला कवर।	4767 नग	26-Aug-24
518	बफर प्लंजर के लिए फेस प्लेट। (बीजी)	2961 नग	26-Aug-24
519	कॉक एएचबी के लिए ओवरहालिंग किट।	668 सेट	26-Aug-24
520	बोगी सेंटर पिवट बॉटम	861 नग	26-Aug-24
521	दो भाग स्लाइडिंग दरवाजे की व्यवस्था	466 नग	30-Aug-24
522	2डी इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल स्टडी फ्लोरोसा कैथ लैब	2 नग	30-Aug-24
523	आर्टिकुलेटेड स्फेरो इलास्टिकरबर बियरिंग	786 नग	2-Sep-24
524	वितरक वाल्व के लिए ओवरहालिंग किट	830 सेट	2-Sep-24
525	माल ढुलाई स्टॉक के लिए फ्रीड पाइप के लिए एयर ब्रेक नली युग्मन।	10898 नग	9-Sep-24
526	ब्रेक पाइप के लिए एयर ब्रेक नली का ऊपलिंग।	14097 नग	9-Sep-24
	उल्टी नीलामी		
41	उन्नत उच्च तन्यता सीबीसी के लिए योक	2266 नग	2-Sep-24

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के संबंध में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr. indianrailways.gov.in पर जाएं। 0382

हमें लाइक करें facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें twitter.com/WesternRly

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95